

भारतीय समाजशास्त्र 1

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

विशेषज्ञ समिति

प्रो. अभिजीत दासगुप्ता दिल्ली अर्थशास्त्र विद्यापीठ दिल्ली विश्व विद्यालय, दिल्ली	प्रो. नीता माथुर समाजशास्त्र विभाग एस.ओ.एस.एस., इग्नू, नई दिल्ली	डॉ. किरनामई भुशी समाजशास्त्र विभाग एस.ओ.एस.एस., इग्नू, नई दिल्ली
प्रो. मेत्रेयी चौधरी सी.एस.एस.एस., जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली	प्रो. अनु अनेजा लिंग और विकास अध्ययन विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली	डॉ. रबीन्द्र कुमार समाजशास्त्र विभाग एस.ओ.एस.एस., इग्नू, नई दिल्ली
प्रो. निलिका महरोत्रा सी एस एस एस,जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली	डॉ. पुष्पेंद्र कुमार समाजशास्त्र विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	डॉ. आर. वाशूम समाजशास्त्र विभाग एस.ओ.एस.एस., इग्नू, नई दिल्ली
प्रो. देबल सिंह रॉय समाजशास्त्र विभाग एस.ओ.एस.एस., इग्नू, नई दिल्ली	डॉ. अभिजीत कुंडु समाजशास्त्र विभाग वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	डॉ. शुभांगी वैद्य अंतर और परा.अनुशासन अध्ययन इग्नू, नई दिल्ली
प्रो. त्रिभुवन कपूर समाजशास्त्र विभाग एस.ओ.एस.एस., इग्नू, नई दिल्ली	डॉ. अर्चना सिंह समाजशास्त्र विभाग एस.ओ.एस.एस., इग्नू, नई दिल्ली	

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

इकाई	लेखक	संपादक (विषयवस्तु, प्रारूप और भाषा)
खंड 1	भारत की समझ : प्रमुख विमर्श	डॉ. अर्चना सिंह
इकाई 1	इंडोलोजिकल विमर्श (डिस्कोर्स)	डॉ. शास्वती भट्टाचार्य, दि. वि /अनु. राजेंद्र पांडेय
इकाई 2	औपनिवेशिक विमर्श	डॉ. शास्वती भट्टाचार्य, दि. वि /अनु. राजेंद्र पांडेय
इकाई 3	राष्ट्रवादी विमर्श	डॉ. प्रफुल्ल कुमार नाथ, असम वि. वि/अनु. राजेंद्र पांडे
इकाई 4	सबाल्टर्न (उपाश्रित) विमर्श	डॉ. प्रफुल्ल कुमार नाथ, असम वि. वि/अनु. राजेंद्र पांडे
खंड 2	भारतीय समाज: एक आलोचनात्मक बहस-I	डॉ. अर्चना सिंह
इकाई 5	जाति	डॉ. शैली भाषांजलि/अनु. डॉ. शास्वत कुमार
इकाई 6	जनजाति	डॉ. थुयंबीना गंगमी/अनु. डॉ. शास्वत कुमार
इकाई 7	गाँव, नगर और शहर	ESO-12, भारत में समाज, डॉ. अर्चना से अनुकूलित
इकाई 8	मजदूर और उद्योग	डॉ. ओतोजित क्षेत्रिमयुम, एन.एल.आई,नोएडा/अनु. डॉ. शास्वतकुमार
इकाई 9	कृषक वर्ग	डॉ. कुसुमलता,सी.सी.एम.जी,जे.एम.आई/अनु.श्री एम.पी कंवल
खंड 3	भारतीय समाज : एक आलोचनात्मक बहस-II	डॉ. अर्चना सिंह
इकाई 10	विवाह, परिवार और नातेदारी	ESO-12, भारत में समाज, डॉ. अर्चना से अनुकूलित/अनु. राजेंद्र पांडेय
इकाई 11	धर्म और समाज	डॉ. कुसुम लता,जामिया मिलिया / अनु. राजेंद्र पाण्डेय
इकाई 12	प्रजाति और नृजातीयता	डॉ. प्रफुल्ल कुमार नाथ,असम वि.वी /अनु. राजेंद्र पाण्डेय
इकाई 13	राजनीति और समाज	ESO-12, भारत में समाज, डॉ.अर्चना से अनुकूलित
इकाई 14	अर्थ व्यवस्था और समाज	डॉ. ओतोजित क्षेत्रिमयुम,एन.एल.आई,नोएडा/अनु. राजेंद्र पाण्डेय

पाठ्यक्रम संयोजक : डॉ. अर्चना सिंह, एस.ओ.एस.एस, इग्नू, नई दिल्ली
प्रधान संपादक : प्रो. एहसानूल हक, सी.एस.एस.एस, जे.एन.यू, नई दिल्ली

ग्राफिक / कवर डिज़ाइन : सुश्री अरविंदर चावला, ए.डी.ए ग्राफिक्स, नई दिल्ली

सामग्री निर्माण

श्री तिलक राज	श्री याशपाल
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)	अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)
एमपीडीडी, इग्नू, नई दिल्ली	एमपीडीडी, इग्नू, नई दिल्ली

जुलाई, 2020

© इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2020

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कृति का कोई भी अंश, मिमियोग्राफ या किसी भी अन्य रूप में, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पुनरुत्पादित नहीं किया जा सकता है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव, एमपीडीडी, इग्नू द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : टेसा मीडिया एण्ड कम्प्यूटर, C-206, A.F.Enclave-II, नई दिल्ली



ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

विषय-वस्तु

	पृ.सं.
खंड 1 भारत की समझ : प्रमुख विमर्श	7
इकाई 1 इंडोलोजिकल विमर्श (डिस्कॉर्स)	9
इकाई 2 औपनिवेशिक विमर्श	21
इकाई 3 राष्ट्रवादी विमर्श	35
इकाई 4 सबाल्टर्न (उपाश्रित) विमर्श	49
खंड 2 भारतीय समाज: एक आलोचनात्मक बहस-I	63
इकाई 5 जाति	65
इकाई 6 जनजाति	79
इकाई 7 गाँव, नगर और शहर	94
इकाई 8 मजदूर और उद्योग	114
इकाई 9 कृषक वर्ग	127
खंड 3 भारतीय समाज : एक आलोचनात्मक बहस-II	145
इकाई 10 विवाह, परिवार और नातेदारी	147
इकाई 11 धर्म और समाज	173
इकाई 12 प्रजाति और नृजातीयता	187
इकाई 13 राजनीति और समाज	200
इकाई 14 अर्थ व्यवस्था और समाज	219
उपयोगी पुस्तकें	233
शब्दावली	234

खंड 1

भारत की समझ : प्रमुख विमर्श

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

पाठ्यक्रम परिचय

भारतीय समाजशास्त्र-1 पाठ्यक्रम समाजशास्त्र की बी. ए. (ऑनर्स) समाजशास्त्र के मुख्य पाठ्यक्रमों में से एक है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा आपको भारतीय समाज, उसके सामाजिक संस्थानों और सामाजिक प्रक्रियाओं के समाजशास्त्र को समझाने की कोशिश की गई है। प्रश्न उठता है, हम सामाजिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन क्यों करते हैं? आगे, किस तरह से यह हमें भारतीय समाज को समझने में मदद करेगा? यद्यपि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इन संस्थानों को सामान्य ज्ञान टिप्पणियों के माध्यम से देखते हैं और अनुभव करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र हमें सामान्य ज्ञान टिप्पणियों और प्रथाओं से समझ बनाने का एक वैज्ञानिक तरीका प्रदान करता है। समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि के माध्यम से, हम आलोचनात्मक इरादे से भारतीय समाज के विभिन्न सामाजिक संस्थानों को समझने का प्रयास करते हैं। हम इन संस्थाओं में परिवर्तन की प्रक्रियाओं और भारतीय सामाजिक संरचनाओं और परंपराओं के संस्थाओं की समझ को बेहतर करने के लिए विभिन्न विमर्शों के माध्यम से उपलब्ध व्याख्याओं का उपयोग करेंगे।

इस पाठ्यक्रम के पहले खंड में, **भारत की समझ: प्रमुख विमर्श**, में हमने विचारों के विभिन्न धाराओं या किस्सों पर चर्चा की है जो आपको भारतीय समाज और इसमें हम आपको इसकी संस्थाओं के बारे में सूचित करेंगे। ये किस्से पुरातात्विक, ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों से भिन्न होते हैं, जिनका उपयोग प्राच्यविदों (ओरिएंटलिस्टों) और भारतविदों (इंडोलॉजिस्टों) द्वारा उपनिवेशवाद से पहले और बाद में दोनों के लिए किया गया था और अभी भी किया जाता है। इसके अलावा, इन प्रमुख विमर्शों, राष्ट्रवादी विमर्श और अंत में, इस पाठ्यक्रम में भारतीय समाज और सामाजिक संस्थाओं की एक सबाल्टर्न (उपाश्रित) समालोचना का विवरण दिया गया है। ये विमर्श आपको भारतीय सामाजिक संस्थाओं को समझने में मदद करेंगे और इस खंड में उसी की एक आलोचना विकसित की गई है। अगले **खंड 2 में भारतीय समाज: एक आलोचनात्मक बहस –I**, में आपको जाति, जनजाति, गाँव, कस्बा और नगर, कृषि वर्ग, उद्योग और श्रम जैसे संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण समझ का विवरण दिया गया है। **खंड 3 में, भारतीय समाज: एक आलोचनात्मक बहस –II** में हमने आपको भारतीय समाज के संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आप इसमें सामाजिक संस्थाओं, जैसे परिवार, विवाह और नातेदारी, धर्म और समाज, प्रजाति और नृजातीयता, राजनीति और समाज, और अंत में, अर्थव्यवस्था और समाज की विस्तृत चर्चा और विश्लेषण दिया गया है। विभिन्न इकाइयों में और इन सभी चर्चाओं में, हमने समाज के इन विभिन्न संस्थाओं और उन परिवर्तनों की व्याख्या करने की कोशिश की है, जिन्होंने समय-समय पर उन्हें आकार दिया है।

इकाई 1 इंडोलॉजिकल विमर्श डिस्कोर्स*

इकाई की रूपरेखा

- 1.0 उद्देश्य
- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 इंडोलॉजी का अर्थ
- 1.3 इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य
 - 1.3.1 भारतीय परिप्रेक्ष्य का प्रभाव
 - 1.3.2 इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य की आलोचना
- 1.4 सारांश
- 1.5 संदर्भ
- 1.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप सक्षम होंगे:

- इंडोलॉजी के अर्थ पर चर्चा करने में;
- 19वीं शताब्दी की शुरुआत में तीसरी शताब्दी पूर्व के बीच भारतीय समाज पर इंडोलॉजिस्ट के विभिन्न दृष्टिकोणों पर विमर्श का वर्णन करने में;
- भारतीय परिप्रेक्ष्य की आलोचना प्रदान करने में।

1.1 प्रस्तावना

इस इकाई में हम आपको इंडोलॉजी का अर्थ समझाएंगे, यह क्या है और यह प्राच्यवादी विचार विमर्श का हिस्सा कैसे है? भारत के समाजशास्त्र के विद्यार्थी, के रूप में आप उन विद्वानों के योगदान से परिचित होंगे, जिन्होंने संस्कृत, फारसी आदि के अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया था, उन पाठों और ग्रंथों दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 19वीं शताब्दी तक भारत में आये विभिन्न यात्रियों द्वारा दर्ज हैं। आप भारतीय समाज के बारे में और अंत में अपने विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में जानेंगे; इस इकाई में इन दृष्टिकोणों की आलोचना का वर्णन किया गया है।

1.2 इंडोलोजी का अर्थ

तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय समाज पर रोमन, बीजान्टिन यूनानी, यहूदी, चीनी, यात्रियों के अवलोकन दर्ज हैं और 1000 ईस्वी से, अरब, तुर्क, अफगान और फारसियों के लिखे गए भारतीय समाज पर अवलोकन दर्ज किए गए हैं।

एक यूनानी इतिहासकार मेगास्थेन्स, 302 ईसा पूर्व में सेलेक्यूस साम्राज्य के संस्थापक सेल्यु कस-1 निक्टर के राजदूत के रूप में सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य की अदालत में

*डॉ. शास्वती भट्टाचार्य, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

भारत आए। मेगास्थेन्स के अनुसार, मगध साम्राज्य के लोग, अपनी राजधानी पाटिलीपुत्र (पटना) के साथ, सात समूहों में विभाजित थे :

- 1) दार्शनिक संस्कार और बलि की धार्मिक क्रिया करते थे
- 2) किसान जो बड़ी जनसंख्या में थे व कर देते थे
- 3) चरवाहा और शिकारी
- 4) कारीगर
- 5) सैनिक
- 6) राजा या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त प्रशासनिक कार्यों के सर्वेक्षक/निरीक्षक
- 7) राज प्रशासन में सभासद और कर निर्धारक अधिकारी।

इंडिका की पुस्तक में भारत के बारे में मेगास्थेन्स के विचार प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित थे, उन्हें किसी स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं था, इसलिए उनके लेखन को बहुत स्पष्टता के साथ नहीं देखा जा सकता था। उन्होंने शहरी राजनीतिक केंद्रों को देखा था लेकिन वह जाति व्यवस्था का जिक्र नहीं करते हैं।

अल-बरूनी (973 ईस्वी-1030 ईस्वी) संस्कृत स्रोतों से परिचित थे और जाति व्यवस्था के चार वर्णों के सिद्धांत का उल्लेख करते हैं, मुगल दस्तावेजों में जाति व्यवस्था के भीतर आंतरिक उप-विभाजन दर्ज है।

बाक्स 1

1443 में, अब्दुर रज्जाक समरकंदी तिमुरी साम्राज्य के बीच राजनयिक संबंध बनाने और भारत में सबसे शक्तिशाली शहर-राज्य के बीच राजनयिक संबंध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर थे। विजय का महान हिंदू शहर विजयनगर, तब अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच रहा था, और तुंगभद्र नदी के दक्षिण में प्रायद्वीप भारत की समृद्ध भूमि को नियंत्रित कर रहा था।

उन्होंने लिखा, 'विजयनगर का शहर जैसा शहर इस दुनिया में कहीं नहीं है।' 'ऐसा ही है कि आँखों की पुतली ने कभी ऐसा स्थान नहीं देखा है, और खुफिया जानकारी को कभी सूचित नहीं किया गया है कि पूरी दुनिया में इसके बराबर कुछ भी नहीं मौजूद है यह विशाल परिमाण और आबादी का शहर है, पूर्ण शासन और आश्रय के राजा के साथ, जिसका राज्य एक हजार से अधिक संघ में फैला है। उनके अधिकांश क्षेत्र समृद्ध हैं, और उनके पास तीन सौ बंदरगाह हैं। उसके पास हजारों हाथी हैं जिनका आकार पर्वतों सा और आकृति दैत्यों सी है साम्राज्य में इतनी बड़ी आबादी है कि इसका विचार करना असंभव होगा...'

अब्दुर रज्जाक विशेष रूप से चारों ओर दृष्टिगत असाधारण व्यक्तिगत संपत्ति पर आश्चर्यचकित थे, विशेष रूप से हर सामाजिक वर्ग के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने हुए आभूषणों पर और परिष्कृत जो रत्नों का व्यापार करते थे : मोती, रूबी, पन्ना और हीरे बेचने वाले स्टाल थे, वह कहता है, व्यापार फल फूल रहे हैं, दुनिया भर से व्यापारियों को आकर्षित कर रहे हैं। वह किले के सात सांद्रिक छल्ले से गुजरा, जिनकी दीवार के साथ अपने स्वयं के गढ़ के साथ, उन्होंने लिखा है। 'एक आदमी की ऊंचाई के बराबर पत्थरों से बना है, जिसमें से एक आधा जमीन के भीतर गया है जबकि दूसरा ऊपर उठा है'। उसके बाद वह खुद को खूबसूरत बगीचों के

क्षेत्र में पाया, जिनके बगीचे से साफ पानी के नालियां और तराशे हुए चिकने पत्थरों से बनी नहरें बह रहीं थीं।

पुर्तगाली प्राकृतिक दार्शनिक गार्सिया दा ऑर्टो (1501-68) विजयनगर में दुनिया के सबसे बड़े हीरे प्रदर्शन पर थे – आसपास सबसे महंगे हीरों के भंडार इलाकों में स्थित थे: 'दो या तीन पत्थर (हीरे) हैं जो विजयनगर के राजा को अत्यधिक लाभ पहुँचाती हैं, उन्होंने लिखा, 'हीरे इस देश के राजा को सर्वाधिक आय अर्जित कराते हैं। कोई भी हीरा जिसकी वजन 30 कैरेट से अधिक है, राजा की संपत्ति होता है। इसके लिए सुश्रुत कर्मियों को खुदाई पर रखा गया है, और यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ पाया जाता है, तो उसे उसके सब बदल जाता है गुजराती उन्हें खरीदते हैं और उन्हें विजयनगर शहर में बिक्री के लिए ले जाते हैं, जहां हीरे के ऊँचे दाम मिलते थे, विशेष रूप से नफीज कहते थे जो मुदरती तौर पर ही नायाब होते थे कहते हैं, है; जबकि पुर्तगाली उन हीरों को महत्व देते हैं जिन्हें पॉलिश किया गया होता है। कैनारसे का कहना है कि जैसे ही एक कुंवारी लड़की एक औरत की तुलना में अधिक मूल्यवान होती है, इसलिए यह नफीज हीरा एक हीरे से अधिक मूल्यवान है इस भूमि में मैंने जो सबसे बड़े हीरे देखा वह 140 कैरेट, एक और 120 कैरेट का था, और मैंने सुना है कि इस भूमि के एक मूल के पास 250 कैरेट्स का भी एक हीरा था मैंने क्रेडिट के योग्य व्यक्ति से सुना था कि उसने विजयनगर में एक छोटे मुर्गी के अंडे के आकार का हीरा देखा था। '

दक्षिणी इतिहास के महान साम्राज्य: पल्लव, चालुक्य और तंजौर के शक्तिशाली चोलसाम्राज्य थे।

विलियम डालेरीम्पल, हम्पी में प्रस्तावना: जॉर्ज मिशेल और जॉन फ़िरट्ज द्वारा गॉड्स एंड किंग्स ऑफ़ किंग्स से उद्धृत:

<http://www.openthemagGzin.com/article/essay/the-44toldhistory-of->

भारत की ऐतिहासिक यात्रा में उपनिवेशवाद एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिसने भारत को आधुनिकता से परिचित कराया। यूरोपीय यात्री लंबे समय से भारत यात्रा पर जा रहे थे और उनके वृत्तांत ने गौरवशाली शब्दों में भारतीय समाज के बारे में बातें की थी। 18वीं शताब्दी वे भारत में, संस्थापित कृषि और बड़े पैमाने पर शिल्प उत्पादन, राजशाही संस्था, आंशिक रूप से लिखित कानूनी व्यवस्था, लेखाजोखा रखने और नियमित मूल्यांकन द्वारा प्रस्तुत और प्रमुख सैन्य बल उपस्थित हैं तथा यूरोपीय समाज के समान राजनीतिक और आर्थिक व्यवसाय भी मौजूद थे, जैसे क्लर्क, कर अधिकारियों, बैंकरों, न्यायाधीश, व्यापारी आदि। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के दोनों पवित्र ग्रंथों के आधार एक जटिल सामाजिक-धार्मिक प्रणाली का प्रयोग पर विवेचन किया जाता था, जिसमें पुजारियों की श्रेणी और पदानुक्रम और धर्म के विद्वान शामिल थे।

सोचिये और करिये 1

शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों जैसे 'शाकुंतलम' के अनुवाद पढ़ें और उस समय के समाज और संस्कृति पर एक पृष्ठ लिखें जो यहाँ या किसी अन्य पाठ में परिलक्षित होता है और अध्ययन केंद्र पर और सहपाठियों के साथ चर्चा करें।

1.3 इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य

भारतवादी दृष्टिकोण ने कुछ अवधारणाओं, सिद्धांतों और ढांचे प्रदान किये जो विद्वानों के दावे भारतीय सभ्यता के अनुसार के उनके अध्ययन से उभर कर आये। उन्होंने मुख्य रूप से एक ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। भारतीय समाज और इसकी संरचना की उनकी समझ बड़े पैमाने पर शास्त्रीय संस्कृत और फारसी ग्रंथों और साहित्य के अध्ययन पर आधारित है। विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने भारत और पश्चिम दोनों प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहन सम्मान भी रखा और सभ्यताओं में निरंतरता को समझने में अधिक रुचि रखते थे।

हालांकि, हम यह नहीं कह सकते कि भारत और भारतीय समाज में रुचि केवल हाल ही में है। कोहन (1990) ने नोट किया कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से विदेशी यात्रियों के छुट पुट वृत्तांत से ले भारतीय इतिहासकारों की 15 वीं शताब्दी तक शासकों को राजदरबारों में हम भारतीय समाज के अवलोकनों से और संस्कृत ग्रंथों के आधार पर अनुशंगी विश्लेषण पर लेखन की श्रृंखला पाते हैं।

यह बात है और कि प्रथम दृष्टि 18वीं शताब्दी के बाद के भारतविदों ने और अधिक व्यवस्थित रूप से भारत का विवरण दिया है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन पुराने लेखों का एक विवरण हमें यह जानने में मदद करता है कि कैसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बाद के युग से भिन्न थी और क्या समानताएं हैं, यानी व्यापक श्रेणियां जिनके द्वारा हम आज भारत को समझते हैं, उन सभी को हम इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में किसी प्रविधि के विचार से वर्गीकृत नहीं कर सकते।

इस प्रकार, भारत की अवधारणा तक निर्माण मेगास्थेन्स (ऊपर वर्णित) जैसे यात्रियों के वृत्तांत में और बाद में अल बरुनी और अबुलफजल जैसे इतिहासकारों के लेखा उपनिवेशवादियों, यानी पुर्तगाली साहसिकों और प्रशासकों, व्यापारियों और मिशनरियों जिन्होंने ब्रिटिश शासन के आगमन तक भारत के बारे में लिखना जारी रखा।

हालांकि ये जब उस समय की प्रचलित संस्कृति के समय विवरण हैं, वे या तो शहरी केंद्रों की सामाजिक प्रणाली की थी परिचालित परिभाषाओं के आंशिक अवलोकनों पर आधारित हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, मेगास्थनीज के लेखन में, मूल भाषाओं को समझने में उनकी असमर्थता के कारण वर्ण सिद्धांत का कोई संदर्भ नहीं मिलता है।

इसके बजाय उनकी भारत की समझ एक वर्ग आधारित समाज की है जो व्यवसायों के आसपास विभाजित है। दूसरी तरफ, संस्कृत स्रोतों के साथ उनकी परिचितता के माध्यम से अल बरुनी और अबुल फजल जाति व्यवस्था के वर्ण सिद्धांत के बारे में जानते थे और यहां तक कि जाति के आंतरिक विभागों को भी मान्यता देते थे। यह तथ्य नातेदारी पर आधारित सामाजिक रूप में जाति संदर्भ में प्रतिबिंबित किया गया है कि वर्ण प्रणाली की पाठ्य समझ दोनों जाति समूहों के रूप में व्यावहारिक परिचालन समझ के साथ सह-अस्तित्व में था। इसके अलावा, जबकि यूरोपीय विवरण मातृवंशीय और बहुपति समूहों के बारे में बताते हैं और उनमें से अधिकतर अस्पृश्यता और सामुदायिक निषेध आदि का महत्व, मौजूद भारतीय समाज, लोगों और संस्कृति के बजाय मुगल अदालतों और राजनीतिक और व्यावसायिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1670 में हिंदू धर्म के डच वृत्तांतों को प्रकाशित किया गया था और जाति व्यवस्था के संक्षिप्त संदर्भ के साथ 1631-1667 के बीच फ्रांसीसी व्यापारी और यात्री जीन बैपटिस्ट टेवेर्नियर का लेख प्रकाशित किया गया था। यह

बहुत बहुत समय बाद अठारहवीं सदी के अंत और उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में हमें भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में अधिक व्यापक वृतान्त मिलते हैं।

इंडोलोजिकल विमर्श
(डिस्कोर्स)



चित्र 1: स्थानीय कलाकार द्वारा लिया गया डचमैन का एक चित्र, उदयपुर मेवाण, ब्रिटिश म्यूजियम 1771-12 ईस्वी

भारतवादी विचारधारा हमें याद दिलाती है कि भारत 'एक' है, जिस तरह से हमें एक पारंपरिक, सांस्कृतिक और उच्च सभ्यता की उपस्थिति मिलती है जो इसकी एकता दर्शाती है। हालांकि, इसकी गलती उस धारणा में निहित है कि भारत की आबादी समरूप है जिससे सभ्यता के निचले या स्थानीय लोकप्रिय स्तर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जा सके।

भारत की 'एकता' जिस के बारे में भारतविद् (indologist) बात करते हैं उसमें स्थानीय, क्षेत्रीय और सामाजिक विविधता भ्रमित या जटिल हो। यह आवश्यकता नहीं है इसके बजाय वे एकता के दावे को मजबूत करते हैं। हकीकत में विमर्श एक पद्धति है क्योंकि अफ्रीका जैसे दुनिया के अन्य हिस्सों के विपरीत, यही एक सांस्कृतिक एकता स्पष्ट रूप में है। भारत के मामले में, एकता विचारों और मूल्यों में निहित है और इसलिए गहरे रूप में यह परिभाषित हो जाती है और (डुमोंट और पोकोक: 1957) है।

चूंकि डुमोंट और पोकोक (1957) का तर्क है, कि शास्त्रीय इंडोलॉजी जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में काम करती है, समाजशास्त्र के वास्तविक अस्थायी तरीकों से भी अलग है, समाजशास्त्र को केवल जीवंत भाषा पर ही नहीं बल्कि शास्त्रीय साहित्य (इंडोलॉजी) से सभी परिचित होना चाहिए। उनके लिए भारत का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन समाजशास्त्र और इंडोलॉजी के सम्बंध में स्थित है। अन्य समाजशास्त्री लुई डुमों, मार्सेल मास, ए.एम होकार्ट जैसे विद्वानों, ने न केवल भारत-यूरोपीय तुलना पर बड़े पैमाने पर लिखा बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण के संदर्भ में एक-दूसरे को संतुलित किया। उदाहरण के लिए, प्रोफेसर डुमो का वर्ण व्यवस्था का अधिक ऐतिहासिक विश्लेषण का जाति पर होकार्ट के काम का पूरकता है, जो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित है।

इंडोलॉजिस्ट के कुछ बुनियादी धारणाएं

- भारत का गौरवशाली अतीत था और इसे समझने के लिए प्राचीन काल के दौरान लिखी गई पवित्र पुस्तकों में वापस जाना चाहिए। भारत के दार्शनिक और सांस्कृतिक परम्पराएं दोनों ही इन ग्रंथों में निहित हैं।

भारत की समझ : प्रमुख विमर्श

- ये प्राचीन पुस्तकें भारतीय संस्कृति और समाज के वास्तविक विचारों को प्रकट करती हैं। भारत के भविष्य के विकास को जानने के लिए इन पुस्तकों को समझना चाहिए।
- प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य और कविता सिखाने के लिए संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए।

बॉक्स 1.1

1787 में बंगाल में विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नथनील हलहेड ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और एशियाटिक्स रिसर्च नामक एक पत्रिका शुरू की। पत्रिका मानव विज्ञान और भारत विद्या की अभिरुचि के लिए समर्पित थी जैसे कि संस्कृत, तुलनात्मक न्यायशास्त्र, तुलनात्मक धर्म आदि। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य थे ग्रीक, लैटिन और अन्य यूरोपीय भाषाओं के साथ संस्कृत के वंश को पहचानने वाले यूरोपीय विद्वान विलियम जोन्स के प्रयास ने न केवल मानव ज्ञान के संग्रह को काफी हद तक जोड़ा; बल्कि उनके काम ने भारतीय लोगों के बीच उनकी अपनी समृद्ध राष्ट्रीय और साहित्यिक विरासत के प्रति पुनः एक रुचि पैदा की। 1789 में उन्होंने शकुंतला संस्कृत में कालिदास द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक, और हितोपदेश, नीतिकथाओं का संग्रह का अनुवाद पूरा किया।

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) इंडोलॉजी क्या है ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारत के समाजशास्त्र में इंडोलॉजी ने कैसे योगदान दिया है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.3.1 भारतीय परिप्रेक्ष्य का प्रभाव

उत्तर प्लासी अवधि (1757 के बाद) में हमें फारसी, संस्कृत और स्थानीय भाषाओं के में वृद्धि पाते हैं जिस भारत के समाज और संस्कृति के व्यापक विश्लेषण को सक्षम बनाया। भारत के इतिहास, दर्शन और धर्म की गहराई और सीमा को उन अनुवादों के माध्यम से जाना जाने लगा है जिन्हें अब प्रारंभिक विद्वानों द्वारा आजमाया जा रहा है। अलेक्जेंडर डॉव, भारत के फारसी इतिहास का अनुवाद करने वाले और हिंदू धर्म की समझ रखने वाले पहले विद्वान ने संस्कृत में लिखे गए हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों के सन्दर्भ न देने की सीमाओं को भी महसूस किया। दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथों को भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में ज्ञान का एकमात्र स्रोत के रूप में महत्व देने की प्रक्रिया में, अनुभवी वास्तविकता पर बहुत कम ध्यान दिया गया था।

भारतविदों ने भारतीय सभ्यता की आध्यात्मिकता को अतिरंजित करके पेश किया और भौतिक संस्कृति का अध्ययन करने के लिए शायद ही कोई प्रयास किया। इसलिए, वे हिंदू धर्म की एक और अव्यवहारिक परिभाषा पर पहुंचे जिसके कई प्रभाव पड़े।

- i) सबसे पहले, इसने ब्राह्मणों की केंद्रीयता और भारतीय समाज में उनके प्रभावशाली स्थिति पर आवश्यकता अधिक जोर दिया, इसके विपरीत साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि कुछ ब्राह्मण राजवंशों, राजनीतिक और सैन्य शक्तियां अन्य समूहों के हाथों में भी थीं।
- ii) दूसरा, इसने भारतीय समाज के एक निश्चित दृष्टिकोण को जन्म दिया जिसने क्षेत्रीय विधिता नहीं थी और न ही समय के साथ हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों का कोई जिक्र था। लोगों के वास्तविक व्यवहार और रीति-रिवाजों के बजाय ग्रंथों के प्रमाण पर संदेहरहित विश्वास और निर्देशात्मक व्यवहार का पालन किया गया। इसलिए भारतीय समाज को नियमों और सामाजिक व्यवस्था की एक प्रणाली के रूप में समझा गया जो सामाजिक परिवर्तन को अस्वीकार करता है।

एडवर्ड (1979) और बर्नार्ड कोहन (1990) दोनों ने बताया कि ज्ञान जाति, नस्ल, जनजाति, अनुष्ठान, प्रथा, कानून, राजनीतिक संस्थानों, 'कालातीत सार' वाले व्यवसायों के साथ 'निश्चित' रूप से समझा गया जो विशेष रूप से हिन्दू धर्म के बारे में संस्कृत में लिखे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथों को भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में ज्ञान का एकमात्र स्रोत के रूप में महत्व देने की प्रक्रिया में, समाज में लोगों की वास्तविक जीवंत यथार्थ पर कम ध्यान दिया गया था।

समाजशास्त्र के भीतर भी भारतीय समाजशास्त्र के कई संस्थापक पिता भी इंडोलॉजी से प्रभावित थे, जैसे बी.एन सील, एस.वी केतकर, बी.के सरकार, जी. एस. घुरये और लुई डूमोंट जैसे अन्य। भारतीय दर्शन, कला और संस्कृति से प्रभावित होने वाले भारतीय लेखन ए. के.कुमारस्वामी, राधाकमल मुखर्जी, डी. पी. मुखर्जी, जी. एस. घुरये, लुई डूमोंट और अन्य जैसे भारतीय विद्वानों के कार्यों में परिलक्षित होते हैं। घुरये हालांकि डब्ल्यू. एच. आर रिर्वर्स के निर्देशन में एक प्रशिक्षित मानवविज्ञानी थे। नदियों, समकालीन घटनाओं के सभी शिष्टाचार - परिधान, वास्तुकला, कामुकता, शहरीकरण, परिवार और रिश्ते, भारतीय जनजातीय संस्कृतियों, जाति व्यवस्था, अनुष्ठान और धर्म जैसे समकालीन घटनाओं को समझने के लिए नियमित रूप से संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथों की ओर झुके। इरावती कर्वे और के.एम कपाडिया जैसे उनके सहयोगी और छात्रों ने भी ऐसा करना जारी समझा। घुर्ये की विधि को बाद में स्वदेशी इंडोलॉजी के रूप में जाना जाने लगा, जो कि सर विलियम जोन्स या मैक्समुलर द्वारा स्थापित ब्रिटिश लेखन के बजाए भंडारकर इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे के इंडोलॉजिस्ट के लेखन से अधिक प्रभावित है।

इस प्रक्रिया में, वह आधुनिक भारत के उदय और इस्लामी और ब्रिटिश शासकों के योगदान को देखने में विफल रहे हैं, बल्कि भारत को वैदिक काल के उत्पाद के रूप में देखते हैं। डुमोंट का इंडोलॉजिकल पूर्वाग्रह वर्ण और जाति के बारे में उनके सिद्धांत में अधिक स्पष्ट है जहां वह भारतीय सभ्यता की एकता को मानते हैं। उनका कार्य, 'होमो हार्डार्किक्स', वर्ण सिद्धांत एक ऐसे रूप में और विचार के रूप में पूरी तरह से इसके इर्दगिर्द वर्ग सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए समानता के अक्ष पर आधारित यूरोपीय समाज के विपरीत भारतीय समाज खिलाफ पदानुक्रम की धुरी पर आधारित है। उन्होंने आगे माना कि जाति की संरचना शुद्धता और प्रदूषण की विचारधारा का परिणाम है जो विचारों और मूल्यों का एक निश्चित और एकीकृत सांचे है। लुई डुमोंट ने एक आधुनिक पश्चिमी समाज की कल्पना की - समूहवादी और समग्र भारत के विपरीत ढली, तर्कसंगत और पूर्णरूप से वैयक्तिक रखती थी (डुमोंट, 1972) की तुलना में अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत थी। इसलिए कई तरीकों से वे एक यूरोपीय-भारतीय वर्ग संस्था का पश्चिम और पूर्व के एक दूसरे के विपरीत हैं, के विचार के साथ इंडोलॉजिस्टो के विचारों का पालन किया।

1970 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान किए गए अध्ययनों में सामाजिक संरचना और रिश्तों, सांस्कृतिक मूल्यों, संबंध, विचारधारा, सांस्कृतिक अदान-प्रदान और जीवन और दुनिया आदि के प्रतीकवाद जैसे विषयों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो इंडोलॉजी के एक उल्लेखनीय प्रभाव को चिन्हित करते हैं। पाठय-सामग्री के आधार पर या तो महाकाव्य, किंवदंतियों, मिथकों, या लोक परंपराओं और संस्कृति के अन्य प्रतीकात्मक रूपों, जीवन और दुनिया आदि के प्रतीकात्मक रूपों के स्पष्ट प्रभाव भी इंडोलॉजिकल पद्धति से निर्दिष्ट हैं।

बोध प्रश्न 2

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) इंडोलॉजिकल स्कूल के मुख्य योगदानकर्ता कौन हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.3.2 इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य की आलोचना

प्राच्यवाद (ओरिएंटलिज्म) का अध्ययन एडवर्ड सैद और रोनल्ड इंडेन द्वारा मुख्य रूप से इतिहास के भीतर क्रांतिकारी सांस्कृतिक प्रभुत्व की समस्या या सत्ता समीकरणों द्वारा चिन्हित एक स्थान के रूप में किया जाता है। हिमाणी बैनर्जी जैसे विद्वान यह भी बताते हैं कि जोन्स और अन्य इंडोलॉजिस्ट के काम मुख्य रूप से भारत पर एक वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करने और औपनिवेशिक शासन को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से निर्देशित थे।

जोन्स पर उनके निबंध में, बैनर्जी (1994) ने टिप्पणी की:

“यद्यपि जोन्स मुख्य रूप से मानववादी हैं – एक अनुवादक, भाषाविद और एक सांस्कृतिक निबंधक हैं - भारत के बारे में ज्ञान और उनके ज्ञान मीमांसा की जांच, सत्ता के एक विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण का खुलासा करती है ... जोन्स का उद्देश्य भारत का पुनर्प्रस्तुतीकरण करना है, यानि इसके इतिहास, संस्कृति और समाज के बारे में ज्ञान का एक संग्रह बनाना है जिस के उनके पुनः प्रस्तुतीकरण को यहीं स्थापित करना है 'भारत' की इस खोज की बढ़ोतरी, एक प्रकार के पौराणिक कथाओं की पराकाष्ठा है, यह भारत को प्राच्य बनाने के लिए व्याख्यात्मक और सम्प्रश्नात्मक ढांचा प्रदान करती है, जिसे उन्होंने भारत, या इंडिया, को 'इंडोलॉजिकल निर्मिति' के "प्रतीकात्मक सांस्कृतिक संविधान" कहा "(1994:19)।

बैनर्जी निरंजन (1994 में 1990:20) को उद्धृत करते हुए जोन्स के कार्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं को एक विधिवेत्ता और अनुवादक के रूप में टिपण्णी की जो औपनिवेशिक शासन को तर्कसंगत बनाने के प्रयास को प्रतिबिंबित करता है।

सर्वप्रथम, यूरोपीय लोगों द्वारा अनुवाद की आवश्यकता पर जोर दिया गया, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी अपने स्वयं के कानूनों और संस्कृतियों के बारे में अविश्वसनीय व्याख्या कर रहे थे। तथा दूसरी बात यह है कि भारतीयों को अपना "स्वयं" का कानून देने के लिए कानून-दाता बनने की इच्छा; तथा आखिरकार भारतीय संस्कृति को शुद्ध करने और इसकी ओर से बोलने की प्रबल इच्छा रखते थे।

समाजशास्त्री ए. आर. देसाई की आलोचनाएं जो भारतीय समाज को संस्कृति के चश्में से देखते हैं और एक पाठय आधारित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, वास्तविक भारत से इसकी असमानताओं, विविधताओं, अंतर वर्ग से दूसरे वर्ग या समप्रदाय और शोषण से काफी दूर हैं।

बोध प्रश्न 3

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) इंडोलॉजिकल स्कूल के खिलाफ मुख्य आलोचनाएं क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

1.4 सारांश

इस इकाई में हमने इंडोलॉजी के अर्थ पर चर्चा की है। इंडोलॉजी भारतीय समाज के अध्ययन की दिशा में प्राच्यवादी दृष्टिकोण का हिस्सा है। यह भारतीय (दक्षिण एशियाई) समाज, इसकी संस्कृति, भाषाओं, साहित्य, इतिहास और राजनीति के अध्ययन को संदर्भित करता है। इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण का प्रभाव यह है कि यह न केवल पाठ आधारित दृष्टिकोण को लेकर भारत के विचार को केन्द्रित करता है बल्कि इसे अकादमिक लक्ष्य के रूप में भी स्थापित करता है जो बाद में शोधकर्ताओं, विचारकों और भारत के समाजशास्त्र

के क्षेत्र को प्रभावित करता है। बर्नार्ड एस कोहन (1990) ने ओरिएंटलिस्ट्स के परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण इस पाठ्य आधारित दृष्टिकोण को समझाने के लिए किया है जिसने भारतीय समाज की तस्वीर को स्थिर, शाश्वत और कभी न बदलने वाला पेश किया।

भारतीय परिप्रेक्ष्य को समझाया गया है। हमने गठित किया कि 'भारतीय समाज के इस दृष्टिकोण में, कोई क्षेत्रीय भिन्नता नहीं थी और परिप्रेक्ष्य, ग्रंथों से प्राप्त प्रतिदर्शात्मक तथ्य के बीच संबंधों पर प्रकाश डालते गया है और बर्नार्ड कोहन (1990) द्वारा उल्लेखित समूह के वास्तविक व्यवहार के रूप में दिखाया गया है।

यह इकाई इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण के सतत प्रभाव का वर्णन करती है जो स्पष्ट करता है कि विद्वान भारत में व्यक्ति की अपेक्षा परम्पराओं और समूहों की भूमिका पर जोर देते हैं सामाजिक संबंधों के आधार के रूप में और धर्म, नैतिकता और दर्शन को सामाजिक संगठन के आधार के रूप में व्यक्त करते हैं।

इंडोलॉजी लोगों के व्यवहार का प्रतिनिधि है या जो लोगों के व्यवहार को एक महत्वपूर्ण तरीके से निर्देशित करता है। इकाई में चर्चा की गई है कि क्यों ड्यूमॉन्ट ने पॉकॉक के साथ इंडोलॉजी और समाजशास्त्र के संश्लेषण पर तर्क दिया।

1.5 संदर्भ

बनर्जी, हिमानी (1994) राइटिंग इंडिया, डूइंग 'आईडीओलोजी' विलियम जोन्स कंस्ट्रक्सन ऑफ इंडिया एज एन आईडीओलोजिकल कैटेगरी फ्रॉम <http://ih.journals.yorku.ca/index.php/ih/article/viewfile/5289/4485> accessed on july25.2017

बर्नार्ड कोहन, द स्टडी ऑफ इंडियन सोसायटी एंड कल्चर इन कोहन एंड सिंगर (एड) स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी (1968, रिप्रिंटेड 2009, रावत पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली)

कोहन, बर्नार्ड 1990 . एन अंथ्रोपोलोजिस्ट एमंग दे हिस्टोरियंस एंड अदर एसेज. ओयूपी दिल्ली

डैलरीपल विलियम, फोरवर्ड इन हम्पी : ऑफ गाड्स एंड किंग्स बाइ जॉर्ज मिशेल एंड जॉन फ्रिज. सोर्स फ्रॉम : <http://www.openthemagazine.com/article/essay/the-untold-historyofhampi>_accessed on 3rd august. 2018

ड्यूमॉन्ट,एल एंड पोकोक,डी. 1957. फॉर ए सोसिओलोजी ऑफ इंडिया ,कंट्रिब्यूशन टु इंडियन सोसिओलोजी,1, पृ. 7-22

इंडेन रोनाल्ड (1990) इमेजिंग इंडिया, इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्लूमिंगटन.

वालरस्टीन, इम्मानुएल. 2000. डज इंडिया एकजिस्ट ? इन द एसेंशियल वलरस्टीन द न्यू यॉर्क प्रेस: न्यूयॉर्क.

1.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

- 1) इंडोलॉजी ऐतिहासिक वृत्तांतों का अध्ययन है, जो संस्कृत, फारसी, अरबी भाषाओं में भारत के सबसे पुराने लेखन के बारे में कई विद्वानों द्वारा आयोजित किए गए हैं, जो भारतीय समाज और संस्कृति को एक संकल्पनात्मक परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते थे।

- 2) कुछ अन्य लोगों की तरह डियुमोंट और पोकाँक (1957) जैसे समाजशास्त्रियों का मानना था कि समाजशास्त्रियों को अपने समाजशास्त्र विश्लेषण में भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए भारतीयों द्वारा प्रदान किए गए शास्त्रीय साहित्य से परिचित होना चाहिए। भारत का एक सामाजिक अध्ययन समाजशास्त्र और इंडोलॉजी के संश्लेषण में स्थित है।

बोध प्रश्न 2

लगभग 15वीं शताब्दी तक भारतीय शासकों की अदालतों में इतिहासकारों की तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हमें भारतीय समाज के प्रत्यक्ष अवलोकनों और संस्कृत ग्रंथों के द्वितीयक विश्लेषण जैसे मेगास्थनीज जैसे इतिहासकारों के द्वितीयक विश्लेषणों के आधार पर लेखन की शृंखला मिलती है। अल-बिरूनी और बाद में अबुल फजल अलामी प्रारंभिक उपनिवेशवादियों, यानी पुर्तगाली साहसिकों और प्रशासकों, व्यापारियों और मिशनरियों जिन्होंने ब्रिटिश शासन के आगमन तक भारत के बारे में लिखना जारी रखा।

18वीं शताब्दी में विलियम जोन्स, हेनरी मेन, मैक्स म्यूलर, और बाद में हेनरी थॉमस कोलब्रुक, अलेक्जेंडर डॉव, अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे ओरिएंटलिस्टों के द्वारा हम भारतीय दृष्टिकोण के रूप में व्यवस्थित निर्मित संयुक्त प्रयास को पाते हैं जिसे भारत के बारे में इंडोलॉजिकल विचार कहते हैं।

बोध प्रश्न 3

भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में पाठ को महत्व देने की प्रक्रिया में इंडोलॉजिस्ट ने समाज की असमानताओं, विविधता, बोली यानी भाषा और शोषण पर थोड़ा ध्यान दिया। उन्होंने भारतीय सभ्यता की आध्यात्मिकता को अतिरंजित किया और भौतिक संस्कृति का अध्ययन करने के लिए शायद ही कोई प्रयास किया।

- सबसे पहले, उन्होंने ब्राह्मणों की केंद्रीयता और भारतीय समाज में उनकी प्रमुख स्थिति पर अत्यधिक जोर दिया।
- दूसरा, उन्होंने भारतीय समाज के बारे में एक स्थिर विचार दिया, जिसमें कोई क्षेत्रीय विविधता नहीं थी समय के साथ ऐतिहासिक परिवर्तनों का जिक्र भी नहीं था।

1.7 शब्दावली

सभ्यता : सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का एक उन्नत चरण।

ज्ञान मीमांसा : ज्ञान का सिद्धांत जो ज्ञान के स्रोत का अध्ययन अपनी प्रकृति, कार्यक्षेत्र और सीमा में करता है।

विचारधारात्मक विचार : विचारों या विचारधाराओं का विज्ञान जो कुछ सामाजिक एवं आर्थिक या राजनीतिक सिद्धांत या प्रणाली को आधार प्रदान करता है।

इंडोलॉजिकल : भारतीय (दक्षिण एशियाई) समाज, इसकी संस्कृति, भाषाएं, साहित्य, इतिहास और राजनीति के अध्ययन को संदर्भित करता है।

ओरिएंटलिस्ट्स : उन विद्वानों को संदर्भित करता है जो एशियाई समाजों, उनकी संस्कृति, भाषाएं, इतिहास, साहित्य और उनकी राजनीति का अध्ययन करते हैं।

भारत की समझ : प्रमुख विमर्श **लिविंग लैंग्वेज** : एक ऐसी भाषा जो रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद लोगों द्वारा बोली जाती है और प्रयोग की जाती है।

पाठ्य आधारित विचार : लिखित पुस्तकें/लेख/दस्तावेज/अभिलेख आदि का अध्ययन करने के बाद गठित विचार या राय।



ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 2 औपनिवेशिक विमर्श*

इकाई की रूपरेखा

- 2.0 उद्देश्य
- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य
- 2.3 मिशनरी परिप्रेक्ष्य
- 2.4 प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य
 - 2.4.1 जनगणना और सर्वेक्षण
 - 2.4.2 गांव और शहर
- 2.5 भारतीय समाजशास्त्र पर विमर्श का प्रभाव
- 2.6 सारांश
- 2.7 संदर्भ
- 2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप निम्न कार्य कर सकेंगे:

- औपनिवेशिक शासन के तहत ज्ञान के व्यवस्थित संगठन के माध्यम से भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन पर चर्चा कर सकेंगे;
- भारतीय समाज पर औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य के तहत मिशनरी और प्रशासनिक विचारों के बीच अंतर कर सकेंगे;
- भारत के समाजशास्त्र को आकार देने में औपनिवेशिक विमर्श के विशिष्ट प्रभावों की व्याख्या कर सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई, इकाई 01 इंडीकोलॉजिकलविमर्श (डिस्कोर्स) में, आपने इस बारे में सीखा कि कैसे इंडीकोलॉजिकल दृष्टिकोण ने अवधारणाओं, सिद्धांतों और ढांचे को प्रदान किया, जो विभिन्न विद्वानों द्वारा भारतीय सभ्यता के अध्ययन से उभरा। उन्होंने मुख्य रूप से एक ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। भारतीय समाज और उसकी संरचना के बारे में उनकी समझ काफी हद तक वेदों, उपनिषदों और पुराणों जैसे शास्त्रीय ग्रंथों और साहित्य के अपने अध्ययन पर आधारित है। भारतीय समाज का एक राय उन ग्रंथों के अध्ययन से उभरी जो ब्राह्मण विद्वानों द्वारा रचित थे और जिन्होंने भारतीय समाज को सामाजिक सांस्कृतिक विविधता विहीन एक स्थिर गतिहीन और कालातीत समाज के रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय समाज को नियमों के एक समूह के रूप में देखा जाता था, जिसका पालन हर हिंदू करता था।

* डॉ. शाश्वति भट्टाचार्य

इस इकाई में आप औपनिवेशिक विमर्श के बारे में जानेंगे, अर्थात् औपनिवेशिक काल में भारत में समाज पर विद्वानों, मिशनरियों और प्रशासन संभालने वाले अफसरों द्वारा परिप्रेक्ष्यों के बारे में जानेंगे।

2.2 औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य

एन बी हालहेड ने हिंदू धर्मशास्त्र (1776) विलियम जोन्स का पहला संकलन प्रस्तुत किया, विलियम जोन्स, कोलेब्रुक अन्य विद्वान थे जिन्होंने भारत पर उल्लेखनीय काम किया। एच. एच. रिसले जिनके अधीन भारत की पहली जनगणना (1872) में हुई, जे. एच. हट्टन अंतिम जनगणना आयुक्त थे जिन्होंने बाद के विद्वानों, जैसे मॉर्गन, मैक्लेनन, लब्बॉक, टाइलर, और फ्रेजर आदि की मदद अपने आंकड़ों में सुधारवश किया।

19वीं सदी की शुरुआत ने भारतीय समाज पर मिशनरियों द्वारा प्रस्तुत काफी मात्रा में साहित्य को देखा जिनमें प्रमुख थे क्लॉडियस बुकानन, विलियम कैरी, विलियम वार्ड, सर जॉन शोर जो हिंदू धर्म के आलोचक थे और भारत में ईसाई धर्म के प्रसार में आशा रखते थे।

पारंपरिक भारतीय समाज के अध्ययन में ब्रिटिश औपनिवेशिक रुचि भारतीय समाज के आगे के अध्ययन की नींव रखने में उपयोगी साबित हुई। इन अध्ययनों का जोर इस बात पर था कि भारत को बेहतर तरीके से कैसे शासित किया जाए।

- अंग्रेजों के आने के बाद 1760 से भारतीय समाज विषयक ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ने लगा।
- भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति में जबरदस्त बदलाव आया।
- भारतीय समाज बदलावों से गुजरा जिसमें उद्योगों की शुरुआत के साथ भारत में आधुनिक युग की शुरुआत शामिल थी। डाक और टैलीग्राफ, रेलवे, आधुनिक शिक्षा और शहरों का विकास, नए व्यवसाय, आदि कुछ प्रमुख विकास थे, जिनसे भारतीय समाज में तेजी से बदलाव हुए।

ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति की प्रक्रिया के बारे में विशेष रूप से अवलोकन किया जा सकता है। बर्नार्ड एस. कोहन (1990) का तर्क है कि अठारहवीं शताब्दी से अमेरिकी भारतीय या अफ्रीकी उपनिवेशों की तुलना में भारत के समाज बहुत अलग स्थिति पेश कर रहे थे, ये थे :

- पूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था,
- राजतंत्र पर आधारित राजनीतिक संस्थान,
- आंशिक रूप से लिखित कानून पर आधारित एक कानूनी प्रणाली,
- कर व्यवस्था,
- अभिलेख रक्षण (Record keeping)
- हिंदू और मुसलमानों दोनों की सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्थाओं का एक समूह था।

उनका तर्क है कि नियंत्रण और आदेश की औपनिवेशिक परियोजना के लिए भारतीय भाषाओं का अध्ययन ब्रिटिश के लिए महत्वपूर्ण था।

क्रोहन 1970 यह भी दावा करता है कि औपनिवेशिक सत्ता का एक कार्यक्षेत्र है जिसका मूल स्थानीय प्रभावों का एक अलग माने था। ज्यादातर यह कानून के क्षेत्र में, वास्तव में विभिन्न प्रकार के औपनिवेशिक समाज को विनियमित करने के बारे में ब्रिटिश धारणाओं के उल्लेखनीय परिवर्तन के लिए जिम्मेदार बन गया। यह न केवल भारतीय समाज के ज्ञान की प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण के प्रारूपों को उभरने में मदद देता है, जो औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा बेहतर तरीके से शासित हो सकता है। केंद्रीय समस्याएं जो सामने आईं और उन्हें समझा जाना था कि एक राजनीतिक-सैन्य प्रणाली कैसे विकसित की जाए, जो भारतीय हाथों में सरकार के दैनिक कामकाज को करता रहे और फिर भी भारतीय विषयों पर निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए एक सफल सूत्र पर पहुंचे।

बॉक्स 2.0

कुछ इंडोलॉजिस्टों ने शासक और शासित के बीच सामान्य आधार खोजने की कोशिश की और समानता की तलाश की। उदाहरण के लिए-

उन्होंने कहा, "भारत के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के माध्यम से यह भी बताया कि पुराने और मुगल भारत का शासन प्रलेखित कानूनों पर आधारित था। राजनीतिक व्यवस्था में मनमानी नहीं थी। विलियम जॉस जैसे एशियाई सोसाइटी के विद्वानों, जैसे मैक्स मुलर आदि द्वारा दिया गया था।

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) भारतीय समाज अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों से कैसे भिन्न था?

.....

.....

.....

.....

.....

2) अंग्रेजों को भारतीय समाज के अध्ययन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?

.....

.....

.....

.....

2.3 मिशनरी परिप्रेक्ष्य

एक राय अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभिक इवेंजेलिकल पादरियों (प्रोटेस्टेंट) जो ईसाई धर्म की शिक्षाओं को बल पूर्वक धर्मांतरण के माध्यम से फैलाने में विश्वास करते थे।

चार्ल्स ग्रांट, सबसे पहले इवेंजेलिकल लेखक थे, जो 1774-1790 में बंगाल में एक वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में कार्य करते थे, ने 1792 में एक पैम्फलेट लिखा था ऑबजर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसायटी एमंग द ऐशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ('महान नैतिकता संदर्भ में, विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन के ऐशियाई विषयों पर समाज की स्थिति पर अवलोकन, और इसे सुधारने के साधनों पर चर्चा')। भारतीय समाज पर उनके विचारों को निम्नलिखित उद्धरण में अभिव्यक्त किया जा सकता है:

उनके कथन से स्पष्ट है कि उनके विचार में ब्रिटिश समाज की तुलना में भारतीय समाज अनिवार्य रूप से असम्मानित असभ्य है और सुधार ही एकमात्र तरीका है, अंग्रेजों को कुछ ऐसा करने की अनुमति दी जाय जो उनके तौर तरीकों का पालन करना सिखाए। इस तरह के 'अधः पतन' के पीछे का मुख्य कारण धार्मिक व्यवस्था में निहित विश्वास था जो भारतीय संस्कृति का आधार है और एकमात्र तरीका जो भारतीयों को उनकी स्थिति से बचा सकता है वह मिशनरी अभियानों के माध्यम से होगा जो भारतीय आबादी को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देगा।

इंडोलॉजिस्ट के विपरीत, संस्कृत ग्रंथों के विशिष्ट अनुवादों का हवाला देकर भारतीय समाज और इसके आचार विचार की निंदा करने का प्रयास किया गया था। इसके अतिरिक्त, सती, परक्ष, बच्चों की गुलामी, गाय की पूजा, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा जैसी कुछ प्रथाओं को समस्याओं और बीमारियों के रोजमर्रा के उदाहरणों के रूप में लिया गया, जिससे भारतीय समाज को भुगतना पड़ा। भारतीय समाज और जाति व्यवस्था का अत्यंत नकारात्मक मूल्यांकन गहराई से किया गया जो उपमहाद्वीप में ईसाई धर्म को स्थापित करने की उनकी आवश्यकता के साथ जुड़ा हुआ था, विशेष रूप से उन लोगों के लिए, जो पदानुक्रम के निचले-स्तर के सबसे निचले स्तर पर थे और जाति व्यवस्था में शोषण महसूस करते थे।

प्रारंभिक मिशनरियों ने जाति व्यवस्था को ईसाई धर्म में धर्मान्तरण रूपांतरण के लिए एक बाधा के रूप में देखा 1816 में एक फ्रांसीसी मिशनरी और एक प्रभावशाली वृत्तान्त के लेखक, अब्बे डुबोइस के लेखन में वर्णों, शिष्टाचार और भारत के लोगों के रीति-रिवाजों और उनके संस्थानों, धार्मिक और नागरिक विवरण केषीर्शक से लिखा गया, जिसमें जाति व्यवस्था का गला घोटना भी शामिल था। भारतीयों के बारे में 'डुबोइस का मानना था कि ब्राह्मणों ने चतुराई से नागरिक संस्था को ब्राह्मणवादी वर्चस्व (फॉरेस्टर, 1980: 26) के लिए समाज की एक पवित्र और अपरिवर्तनीय विशेषता में बदलकर जाति व्यवस्था का निर्माण किया है (पुस्तक 1 एमएसओ 004, इग्नू, 2005, पृ. 61 से उद्धृत)।

यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि जाति व्यवस्था की आलोचना इसलिए की गई क्योंकि मिशनरियों को लगा कि इसने हिंदुओं को ईसाइयों में परिवर्तित करने के उनके प्रयासों को विफल कर दिया है। धर्मांतरण के बाद भी कई हिन्दू जाति के नियमों के अनुसार चलते रहे।

दिलचस्प बात यह है कि आम तौर पर हिंदू समाज को भ्रष्ट करने वाले सबूत की तलाश में, इन मिशनरियों ने भारतीय समाज के अनुभवजन्य अध्ययन में प्रमुख योगदान दिया। इसके अलावा, बाइबिल के अनुवाद की आवश्यकता ने भारतीय भाषाओं के समाजिक-भाषिक अध्ययन के लिए प्रेरित किया। बदले में इसने विभिन्न जाति और व्यावसायिक समूहों की जीवित वास्तविकताओं के अधिक व्यवस्थित और लिखित विवरणों को जन्म दिया। मिशनरियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में भी मदद की। वे जंगलों में आदिवासियों के बीच, सुदूर क्षेत्रों में काम करने गए और कमजोर और गरीबों के लिए उत्साह के साथ काम किया।

हालांकि उनके विश्लेषण में, जबकि मिशनरियों ने भारतविदों और बाद में प्राच्यविदों (पूर्वी दुनिया के विद्वानों) के साथ भारतीय समाज के मुख्य सिद्धांतों के बारे में सहमति व्यक्त की, दोनों ने राजनीतिक संगठन, भूमि कार्यकाल, वास्तविक कानूनी प्रणाली और वाणिज्यिक संरचना के तथ्यों को सही या सुधार करने का प्रयास नहीं किया। प्राच्यविदों और मिशनरियों ने स्वीकार किया और सहमति व्यक्त की:

- धार्मिक विचार और व्यवहार सभी सामाजिक संरचना को रेखांकित करते हैं;
- पवित्र पाठ के ज्ञान के नियंत्रण के माध्यम से पवित्र परंपरा के अनुचर के रूप में ब्राह्मणों की प्रधानता; तथा
- चार वर्णों के ब्राह्मणवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया और चार वर्णों के सदस्यों के विवाह के माध्यम से अंतर मिश्रण में जातियों की उत्पत्ति देखी गई (कोहेन 1968)।

अंतर मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति के उनके मूल्यांकन में है। जबकि प्राच्यविद और भारतविद (इंडोलॉजिस्ट) में एक प्राचीन भारतीय सभ्यता की अत्यधिक प्रशंसा थी और उस आदर्श से भारतीय समाज के पतन से बहुत आहत थे, मिशनरियों का मानना था कि भारतीयों का कोई गौरवशाली अतीत नहीं था और यह हमेशा गौरबराबरी से भरा रहा है।

कोहेन के अनुसार, मिशनरियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इंडोलॉजिस्ट और प्राच्यविद (ओरिएंटलिस्ट) के विपरीत, जो उच्च वर्ग की पृष्ठभूमि और बेहतर शिक्षित थे, मिशनरी, विशेष रूप से बैपटिस्ट ब्रिटिश समाज के निचले पायदान से आए थे, अपने स्वयं के और निश्चित रूप से भारतीय समाज में सुधार के लिए उनमें उत्साह था। वे इंडोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्टों के विपरीत ईसाई धर्म के पक्ष में सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए दृढ़ थे जिन्होंने भारतीय पारंपरिक प्रणाली के लिए एक निश्चित सम्मान रखा।

बॉक्स 2.1

विलियम कैरी ने बंगाली लैंग्वेज जिसे 1801 में श्रीरामपुर प्रेस से प्रकाशित किया गया था, यह शायद भारतीय भाषा का पहला समाजशास्त्रीय अध्ययन है।

रॉबर्ट कैल्डवेल का अध्ययन "कम्पैरेटिव ग्रामर ऑफ द्रविडियन ऑट साउथ इंडियन फ़ैमिली ऑफ लैंग्वेजिज" द्रविडियन या दक्षिण भारतीय परिवार की भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण का अध्ययन द्रविड़ भाषाओं का पहला व्यवस्थित विवरण है और दक्षिण भारत की राजनीति पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव था।

बोध प्रश्न 2

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) मिशनरी दृष्टिकोण क्या था? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

भारत की समझ : प्रमुख विमर्श 2) मिशनरी परिप्रेक्ष्य की तुलना ओरिएंटलिस्टों और भारत के वैज्ञानिकों से करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.4 प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य

प्रशासकों द्वारा भारतीय समाज की व्याख्या, ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित और उपयोगितावादी तर्कवाद द्वारा प्रेरित और अधिक व्यावहारिक और अधिक मामला-संबंधी था। उनका उद्देश्य भारतीय संसाधनों का दोहन करने के लिए भारतीय समाज को समझना था।

प्रशासकों ने ऐसी श्रेणियां विकसित करने की मांग की, जो भारत के मूल निवासियों के जीवन से संबंधित उनके विचारों और कार्यों को क्रमबद्ध करने में उनकी मदद करें, जो इसे जटिल बनाने वाली विशाल जटिलताओं से बचते हैं। उदाहरण के लिए, बी.एच. बडेन-पोवेल (संदर्भ) ब्रिटिश भारत की भूमि प्रणाली के तीन खंड (1892) केवल आंकड़ों का संकलन नहीं था, बल्कि भारतीय गाँव की प्रकृति और इसके संसाधनों के संबंध में तर्कों की एक श्रृंखला थी, इन संसाधनों पर राज्य और उसकी ज़रूरतों से भी संबन्धित थी। बैडेन-पोवेल ने माना है कि ज़मीन या भूमि जो उत्पादन से जुड़ा आमतौर पर उसके दो दावेदार होते हैं। राज्य और भू-स्वामी उन्होंने कहा कि सरकार ने "प्रत्येक होल्डिंग की थ्रेसिंग फ्लोर पर वास्तविक अनाज के ढेर का एक हिस्सा लेकर" अपना राजस्व प्राप्त किया। इस हिस्से के संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और अनाज के ढेर के बीच मध्यस्थों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित हुई। वे अपनी बारी में जमीन या इसके उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व/कब्जे की अलग-अलग स्थिति का दावा करते हैं। इसके अतिरिक्त, भूमि पर अधिकार पारम्परिक व्यवस्था द्वारा स्थापित किए गए थे।

भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विद्वानों के प्रशासकों नियुक्त किया, उदाहरण के लिए, पूर्वी भारत में रिस्ले, डाल्टन और ओ'मले, उत्तरी भारत में क्रुक्स ने भारत की जनजातियों और जातियों के बारे में विश्वकोष लिखा, जो आज जीवन के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करते हैं और संबंधित क्षेत्रों के लोगों की संस्कृति के बारे में भी बताते हैं। इन अध्ययनों का उद्देश्य प्रभावी औपनिवेशिक प्रशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत में जातियों और जनजातियों के बारे में वर्गीकृत विवरणों के साथ सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को परिचित करना था।

महान ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट सर विलियम जोन्स का योगदान बहुत बड़ा था क्योंकि उन्होंने संस्कृत और इंडोलॉजी का अध्ययन शुरू किया था और 1787 में उन्हें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का श्रेय जाता है। 1794 में जोन्स द्वारा मनु के कानून का भी अनुवाद किया गया था।

1757 से 1785 की अवधि एक ऐसा समय था जिसमें बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को एक प्रशासनिक प्रणाली विकसित करनी थी जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक, सैन्य और वाणिज्यिक गतिविधियों के निर्वहन के लिए नियमित रूप से आय का उत्पादन करने में सक्षम थी। कंपनी को लाभ प्रदान करना भी एक अन्य उद्देश्य था। भू-राजस्व के मूल्यांकन और नियमित संग्रह के लिए भारतीय समाज की संरचना के बारे में काफी ज्ञान की आवश्यकता थी। तदनुसार, बंगाल में भूमि के कार्यकाल की प्रकृति के बारे में पूछताछ पिछले शासकों के दस्तावेजों और अभिलेखों को एकत्र करके की गई थी। इसके अलावा, कुछ ब्रिटिश, आधिकारिक और गैर-आधिकारिक, ने अपनी जिज्ञासा से कुछ हद तक उद्देश्यपूर्ण शैली में भारतीय समाज पर अध्ययन और लेखन शुरू किया। उदाहरण के लिए, विलियम टेनेंट, एक सैन्य पादरी अपने दो खंड के काम में भारतीय मनोरंजन: मुसलमानों और हिंदुओं की घरेलू और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से सख्त विरोधाभासों (1804) व्यक्तिगत टिप्पणियों पर उनकी जानकारी के आधार पर, 'कई बुद्धिमानों की बातचीत और लेखन मूल निवासी 'और' सैन्य नौकरों के साथ मौखिक बातचीत 'के आधार पर की।

बॉक्स 2.2 इम्पीरियल गजट (Imperial Gazette)

संक्षेप में, उस समय उपलब्ध शास्त्रीय और मानवशास्त्रीय तकनीकों का उपयोग करना, अर्थात् प्रमुख देशी/स्थानीय मुखबिरों के साथ अवलोकन और साक्षात्कार द्वारा। विशेष दस्तावेज और अन्य जैसे कि एच.टी. कोलब्रुक की पर हसबैंडरी एंड इंटरनल कामर्स ऑफ बंगाल द्वारा दिया गया ग्रामीण समाज का विस्तृत और सावधानीपूर्वक वर्णन है।

2.4.1 जनगणना और सर्वेक्षण

लेकिन ये शुरुआती कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में तेजी से वृद्धि के कारण अपर्याप्त साबित हुए और ब्रिटिश लोग भारत की विविधता, इतिहास, राजनीतिक रूपों, भूमि के कार्यकाल की प्रणालियों और धार्मिक प्रथाओं के बारे में जागरूक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि समाजशास्त्रीय सूचनाओं की अपेक्षाकृत बेतरतीब रिपोर्टिंग को अधिक व्यवस्थित किया जाना चाहिए और वह क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा समर्थित होना चाहिए, जिसका लक्ष्य बेहतर और अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करना का अर्जन था। इनमें से सबसे पहला और प्रसिद्ध डॉ फ्रांसिस बुकानन का योगदान था। उन्होंने 1807 में एक व्यापक सर्वेक्षण किया था जो कभी भी पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुआ था, लेकिन कई मायनों में अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज के सभी पहलुओं के बारे में आधिकारिक और विद्वत्तापूर्ण सूचना इकट्ठा करने, मिलान करने और प्रकाशित करने के लिए किए गए निरंतर प्रयास के वे अग्रदूत थे। यह उन प्रयासों में है कि हम भारत के एक समाजशास्त्रीय इकाई के उद्भव के बारे में जान पाते हैं। उदाहरण के लिए, जाति के 'आधिकारिक' दृष्टिकोण ने इसे एक अनुभवजन्य श्रेणी के रूप में माना, एक 'ठोस' और मापनीय और अब से अधिक इसमें परिभाषित करने योग्य विशेषतायें थी जैसे कि:

- सगोत्रीय या सजातीय विवाह (खुद की जाति और/या उपजाति के भीतर शादी)
- सहभोज (एक साथ खाना) नियम,
- निश्चित व्यवसाय,
- सामान्य अनुष्ठान व्यवहार।

जनगणना की कवायत ने ब्रिटिश प्रशासन के उद्देश्य के लिए 'सामाजिक जीवित (यानि वास्तविक जीवन में घटित होने वाली) वास्तविकता' से जाति की 'निश्चित' श्रेणी बनाई। लॉर्ड मेयो के तहत 1872 की पहली जनगणना मुख्य रूप से एक अभ्यास था जहां मुक्त वाले प्रश्न पूछे गए थे, और धर्म, जाति और नस्ल की श्रेणियों का उपयोग किया गया था।

एकत्र किए गए डेटा को एक जाति को दूसरे से अलग करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण एच.एच. रिस्ले का है जिसमें उन्होंने जनगणना के आंकड़ों की मदद से 2000 विषम जातियों को घटाकर, उनके सात प्रकार निश्चित किये थे:

- 1) आदिवासी;
- 2) कार्यात्मक;
- 3) सांप्रदायिक;
- 4) संस्करण द्वारा गठित जातियां;
- 5) राष्ट्रीय जातियाँ;
- 6) प्रवास द्वारा गठित जातियां; तथा
- 7) परिवर्तित रीति-रिवाजों द्वारा बनी जातियां।

इस तरह की विस्तृत जनगणना से जो प्रश्न उभर कर आए, वे समाजशास्त्रीय अर्थों में जाति की उत्पत्ति और कार्यक्षमता के संबंध में थे, जो कि ओरिएंटलिस्टों और कुछ भारतविदों द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक मूल के प्रश्नों से भिन्न थे।

इसके बाद, जाति के आधिकारिक शोधकर्ताओं ने हालांकि यह स्वीकार किया कि जाति की उत्पत्ति ब्राह्मणवादी सिद्धांत में निहित है, जिसे वे जाति के अधिक कार्यात्मक, कुछ हद तक 'दृष्टिकोण' के रूप में मानते हैं। नेसफील्ड ने जाति को श्रमविभाजन के जड़ से उभरने वाला माना और जोकि व्यवसाय व्यवस्था में निर्धारित केंद्रीय कारक माना। रिस्ले ने जाति के नस्लीय मूल के लिए तर्क दिया। इब्सेट्सन ने 'आदिवासी मूल' में जाति के गठन में प्रमुख जोर देखा। जे.एच. हटन ने चौदह कारकों में स्पष्ट कारकों की एक सूची तैयार की, जिसमें जाति व्यवस्था के संभावित उद्भव और विकास के योगदान का संकेत दिया गया है। आधिकारिक 'दृष्टिकोण केवल उन तरीकों का एक विस्तार नहीं था जिसमें मात्र जानकारी एकत्र की गई थी, बल्कि यह 1870-1910 की अवधि के मानवशास्त्रीय हितों और सिद्धांतों को भी दर्शाता है। जाति व्यवस्था के बारे में लिखी गई सामान्य सैद्धांतिक पुस्तकें संक्षेप में मॉर्गन, मैकलेनन, लुबॉक, टाइलर, स्टार्क और फ्रेजर के कार्यों को दर्शाती हैं। जिसमें क्षेत्र आधारित अध्ययनों से एकत्र किए गए रीति-रिवाजों, मिथकों, कहावतों और प्रथाओं के तथ्यों के बारे में कुछ सामान्य मानवशास्त्रीय समाधान पर पहुंचने का प्रयास था।

हालांकि 1901 में रिस्ले के तहत एक क्षेत्र आधारित नृवंशविज्ञान अनुसंधान सर्वेक्षण के लिए पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था और यह आधार इस आधार पर उचित था कि "भारत में आदिम मान्यताओं और उपयोग पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे या बदल जाएंगे" और "कानून के प्रयोजनों के लिए," न्यायिक प्रक्रिया, अकाल राहत, स्वच्छता और महामारी की बीमारी से निपटने और निष्पादित कार्रवाई के लगभग हर रूप में प्रस्तुत करने के लिए "(कोहन 1990: 157)। यह कार्यसूची आखिरकार राज के हित को सही मायने में और भारत को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए प्रमाणित करता है। यह सर्वेक्षण बाद में 1901 की जनगणना के एक हिस्से के रूप में विकसित हुआ जिसमें जातियों और उप-जातियों का विस्तृत वर्गीकरण था।

2.4.2 गाँव और शहर

जाति के अलावा, भारत का प्रशासनिक विचार 'गाँव' की श्रेणी पर आधारित था। विकसित और अग्रगामी दृष्टिकोण यह था कि भारत मुख्य रूप से गाँवों से बना था। चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीयों को "गाँव समुदायों" में रहने वाले के रूप में वर्णित किया, जो "छोटे गणराज्य हैं, जिनके पास लगभग हर चीज है जो वे उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं और लगभग किसी भी विदेशी संबंधों से स्वतंत्र हैं" (कोहन 1971 पुनर्मुद्रण 2000: 86)। इसलिए गाँवों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में देखा जाने लगा। इस मिथक के निर्माण और इसकी परिधि में तीन बौद्धिक-सांस्कृतिक किस्में पाई जा सकती हैं। पहला ब्रिटिश अतीत का रोमांटिक, आदर्शवादी और विकासवादी मिथक है - 'खुशहाल किसानों से घिरे देश के रूप में 'निजी संपत्ति के उत्थान के लिए सांप्रदायिक संपत्ति रखने वाले चरण से समाज के विकास के बारे में मार्क्सवादी धारणाएँ और इसलिए भारत संपत्ति के स्वामित्व के सांप्रदायिक चरण के रूप में पिछड़ा हुआ है; राष्ट्रवादी विचार जो एक रमणीय अतीत के विचार को पुष्ट करते हैं ताकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सफल आलोचना की जा सके।

जाति 'और' गाँव 'के दृष्टिकोण ने मिलकर ब्रिटिश शासकों को राजस्व कानूनों को बनाने में मदद की, जमींदारों के वर्ग का निर्माण किया और व्यावसायिक कृषि प्रथाओं को भी लागू किया।

बॉक्स 2.3: मैकेंजी का संग्रह

"कोलिन मैकेंजी, भारत के पहले सर्वेक्षक जनरल ये उन्होंने हैदराबाद और मैसूर और दक्षिणी प्रायद्वीप के अन्य क्षेत्रों से बने नक्शों और उनके सहयोगियों के पूर्ति के लिए कथनों और तथ्यों को एकत्र करने में रुचि दिखाई। अपनी पहल पर और अपने स्वयं के संसाधनों के साथ उन्होंने ब्राह्मण सहायकों के एक समूह को काम पर रखा और प्रशिक्षित किया, जिन्होंने उन्हें भारत के राजवंशों, मुख्यतः परिवारों, जातियों, गाँवों, मंदिरों, मठों के साथ-साथ स्थानीय परंपराओं और धार्मिक दार्शनिक ग्रंथों को इकट्ठा करने में मदद की। फारसी, अरबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मल्यालम और हिंदी में अनुबाद भी किया।

मैकेंजी के स्थानीय एजेंटों के पत्रों और डायरियों से, उन शुरुआती शोध सहायकों, या औपनिवेशिक नृवंशविज्ञान और इतिहास लेखन की 'मूल जानकारी' से हम निश्चित रूप से सीखते हैं कि एकत्र करने की प्रक्रिया कुछ भी लेकिन तटस्थ थी, कि ज्ञान का समाजशास्त्र औपनिवेशिक लेकिन शायद ही पूर्व-औपनिवेशिक हो सकता था। सबसे पहले, यह स्पष्ट है कि ये एजेंट, खुद ब्राह्मणों ने माना कि ज्ञान के उपयोगी होने के लिए जरूरी है कि उसे ब्राह्मणों के माध्यम से ही प्रदान की जाए जब भी कोई एजेंट एक नए शहर में गया, तो वह ब्राह्मणों की तलाश के माध्यम से ही पुस्तकों को देखा (पृ. 128-129)।

मैकेंजी के स्थानीय एजेंटों के पत्रों और डायरियों से, उन शुरुआती शोध सहायकों, या औपनिवेशिक नृवंशविज्ञान और इतिहासलेखन की 'मूल जानकारी' से हम निश्चित रूप से सीखते हैं कि एकत्र करने की प्रक्रिया कुछ भी लेकिन तटस्थ थी, कि ज्ञान का समाजशास्त्र औपनिवेशिक लेकिन शायद ही पूर्व-औपनिवेशिक हो सकता था। सबसे पहले, यह स्पष्ट है कि ये एजेंट, खुद ब्राह्मणों ने माना कि ज्ञान के उपयोगी होने के लिए जरूरी है कि उसे ब्राह्मणों के माध्यम से ही प्रदान की जाए जब भी कोई एजेंट एक नए शहर में गया, तो वह ब्राह्मणों की तलाश के माध्यम से ही पुस्तकों को देखा (पृ. 128-129)।

ये ब्राह्मण अनुसंधान सहायक इस प्रकारके थे और एक जटिल सामाजिक वास्तविकता के जरिये वास्तविक में विदेशियों के एजेंट थे। एक तरफ, उन्होंने ज्ञान के ब्राह्मण समाजशास्त्र का निर्माण और प्रतिनिधित्व किया, जो पहले से ही औपनिवेशिक संस्थानों और भारतीयों के लिए कानूनी कोड के निर्माण में अच्छी तरह से प्रलेखित है, लेकिन जिसने गतिहीनता की एक विस्तृत शृंखला भी स्थापित की जिसके परिणामस्वरूप उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के अंत में भारत में सांप्रदायिकता और कभी-कभी तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलगाववादी विरोधी ब्राह्मण आंदोलनों के कारण राष्ट्रवाद का परचम लहराया। दूसरी ओर, वे ब्रिटिशों के और ब्रिटिशों के पक्षाधर एजेंट थे, जिनको ग्रंथों, परंपराओं, ज्ञान, विरोधी तथ्यों आदि को सौंपने के निहितार्थ के बारे में अक्सर काफी और न्यायोचित चिंता थी " (पृ. 12 9-130, डर्क 1997)।

हेनरी मेन और बैडेन-पॉवेल द्वारा भारतीय गांवों पर कई शोध अध्ययनों के बावजूद, जिसमें ग्रामीण स्तर पर संघर्ष, भारत के भीतर संरचना और संस्कृति दोनों के संदर्भ में गांवों के क्षेत्रीय रूपांतर आदि पर चर्चा हुई, गांवों के बारे में श्रेणीगत और वैचारिक सोच स्थिर रही, उस चरण जहाँ पर मानव समाज की विकासवादी प्रगति में सिर्फ एक 'प्रकार' था। इसने गाँव में आंतरिक राजनीति, सामाजिक संबंधों के सवालों, धन वितरण के ढांचे से ध्यान हटाया। वास्तविकता यह है कि सामाजिक नृविज्ञान के छात्र के रूप में भी वे भारतीय गांवों में जीवन की वास्तविक स्थितियों में दिलचस्पी नहीं रखते थे, किन्तु उस समय के सामाजिक सिद्धांत से प्राप्त सामान्य सैद्धांतिक प्रश्नों में उनकी रुचि थी।

उन्नीसवीं शताब्दी के बाद के दशकों में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अकाल, दंगे, भूमि अलगाव आदि की कई उभरती हुई समस्याएं भी पाते हैं, जो औपनिवेशिक अफसरों को गहराई से परेशान किया है, जिससे गाँव की भारत से कुछ हद तक सरल समझ बनती है। नतीजतन, हम अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों के साथ-साथ जमीनी स्तर के दोषों को ठीक करने के लिए प्रशासनिक और वैधानिक परिवर्तनों के लिए भी सुझाव देते हैं। इसलिए हम हेरोल्ड मान की तरह एक ही मांब से अध्ययन करते हैं जो "एक ही गांव के निकट अध्ययन द्वारा कई आर्थिक और कृषि प्रश्नों के बारे में आंकड़ों पर आधारित है।

उपनिवेशवादियों ने भारत में शहरी ढांचे की समझ पर भी पहुंचने का प्रयास किया। वाल्टर हैमिल्टन और रॉबर्ट मोंटोगोमरी मार्टिन दोनों ने क्रमशः सन 1820 और 1855 में अनुमानित जनसंख्या वाले शहरों की सूची दी लेकिन वास्तविकता से कोई भी प्रतिबिंबित नहीं हुआ। इन शुरुआती पर्यवेक्षकों ने बड़े शहरों की आबादी को बहुत अधिक महत्व दिया, ज्यादातर क्योंकि यूरोपीय आंखों ने सड़कों पर भीड़ और भीड़भाड़ देखी। संकरी गलियाँ और इमारत जो गली के किनारे तक हैं; बाजारों और तीर्थ स्थानों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है और इसलिए उन्हें किसी भी निर्णायक आंकड़े तक पहुंचना असंभव लगा। कोहन (1970) का मत है कि आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में रहने वाले शहरी लोगों के स्वभाव और परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है। हालांकि याद रखना चाहिए कि भारतीय शहरों की प्रकृति अत्यधिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था और विदेशी समाज के शहरों की तुलना में बहुत अलग थी। भारतीय शहरों में चार प्रमुख कार्य थे:

- क) आर्थिक - विपणन, व्यापार, वाणिज्य और शिल्प उत्पादन के लिए एक केंद्र के रूप में;
- ख) सैन्य, रक्षा उद्देश्यों के लिए किलों या दीवारों वाले क्षेत्रों के साथ सैन्य केंद्र;
- ग) राजनीतिक जीवन के केंद्र के रूप में राजनीतिक और

घ) धार्मिक-यानी अनुष्ठान विशेषज्ञों, विद्वानों और भक्तों के साथ पवित्र केंद्रों के रूप में।

यह याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हालांकि सभी चार कार्य ज्यादातर एक साथ पाए जाते थे, शहर अपने वर्चस्व वाले कार्य में भिन्न थे। साथ ही अधिकांश उत्तरी और कई दक्षिणी शहरों को राजनीतिक विचारों से बाहर स्थापित किया गया था, क्योंकि नियंत्रण के वे रणनीतिक केंद्र थे। उसी समय, उन्नीसवीं सदी के शुरुआत में शहरों में विभिन्न जीवन शैली थी, महानगरीय, स्थानीय और क्षेत्रीय, बनारस या काशी जो सबसे पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जीवंत शहर होने के लिए अनुकरणीय था और अभी तक सबसे अधिक महानगरीय शहर माना जाता है।

बोध प्रश्न 3

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) प्रशासनिक दृष्टिकोण क्या था? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारतीय समाज को समझने में जनगणना और सर्वेक्षण ने अंग्रेजों की मदद कैसे की?

.....

.....

.....

.....

.....

3) अंग्रेजों ने भारतीय ग्राम और शहरों को किस दृष्टि से देखते थे?

.....

.....

.....

.....

.....

2.5 भारतीय समाज शास्त्र पर औपनिवेशिक विमर्श का प्रभाव

ब्रिटिश शासकों की रुचि ने भारत पर शोध को जन्म दिया। भारतीय समाज और सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न पहलुओं, जैसे जाति, परिवार, विवाह, अनुष्ठान समारोह आदि के बारे में विवरणों का एक विशाल निकाय एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण किये गये। इन सूचनाओं

का उपयोग विभिन्न विद्वानों द्वारा अध्ययन करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्र में अध्ययन के लिए इनका उपयोग किया गया था। जनगणना के आंकड़ों और इंपीरियल गज़ेट्स दोनों ने सामाजिक मानवविज्ञानी और समाजशास्त्रियों को भारतीय समाज का अध्ययन करने में मदद की। गाँव पर किए गए कई अध्ययन उनके प्रभाव में थे। भारत के मानवशास्त्रीय अध्ययन में दोनों रुचि, विशेष विषय वस्तु, कार्यप्रणाली और सिद्धांतों के संदर्भ में और भारत में प्रशासन, गाँव, शहरों के लिए एक श्रेणी के रूप में जाति का इन पर प्रभाव पाते हैं। भारतीय समाज के अध्ययन में ब्रिटिश औपनिवेशिक रुचि को बढ़ाने में मिशनरियों और प्रशासन की भूमिका भारतीय समाज के आगे के अध्ययन की नींव रखने में उपयोगी साबित हुये हैं।

2.6 सारांश

इस इकाई में हमने चर्चा की है कि औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज के अध्ययन को कैसे प्रभावित किया है। औपनिवेशिक विख्याने को मिशनरी दृष्टिकोण में विभाजित किया गया, जो प्रारंभिक मिशनरी दृष्टिकोण के लेखन से विकसित हुआ था तथा जो 18 वीं शताब्दी हुआ था प्रशासनिक दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य प्रभावी औपनिवेशिक नियंत्रण सुनिश्चित करना था। अंग्रेजों द्वारा किये गये विस्तृत सर्वेक्षण, जनगणना की जानकारी और अन्य अध्ययनों ने भारतीय समाज के बारे में ज्ञान की प्रणाली को आकार देने में मदद की और उसके आधार पर कई क्षेत्रों में आगे अनुसंधान किया गया है

2.7 संदर्भ

डर्क्स एन बी 2001, कास्ट्स ऑफ माइंड: कालोनियलिज़्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, परमानेंट ब्लैक, न्यू डेलही

इंडेन, रोनाल्ड , 1990 इमेजनिंग कोहन, बर्नार्ड 2000 (1971). इंडिया: द सोसल अंथ्रोपोलोजी ऑफ ए सिविलाइजेशन. ओयूपी

विद्यार्थी, एल. पी (1976) राइज़ ऑफ अंथ्रोपोलोजी इन इंडिया, कांसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, डेलही

सोसिओलोजी इन इंडिया, 2005 बुक 1 एमएसओ 004 इन्दिरा गांधी नेशनल ओपेन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोसल साइंसेस, न्यू डेलही इंडिया, बेसिल ब्लाकवेल लिमिटेड ,कैम्ब्रिज, मास .

दासगुप्ता, बिप्लब 2003 , द कालोनियल पोलिटिकल पर्सपेक्टिव, पी. पी. सोसल साइंटिस्ट., वॉल. 31, नंबर ¾ (मार्च - अप्रैल 2003, पृ. 27-56)

2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

- 1) भारतीय समाज ने भारत में अठारहवीं शताब्दी के बाद से अमेरिकी भारतीय या अफ्रीकी उपनिवेशों की तुलना में बहुत अलग स्थिति पेश की जैसे यहां पर:
 - क) पूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था थी,
 - ख) राजतंत्र पर आधारित राजनीतिक संस्थान,
 - ग) आंशिक रूप से लिखित कानून के आधार पर एक कानूनी प्रणाली,
 - घ) कराधान,

च) रिकॉर्ड कीपिंग और

छ) हिंदू और मुस्लिम दोनों की सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्था का स्थापित थी।

- 2) 'अलग' प्रकार के औपनिवेशिक समाज को नियमित करने के लिए, अंग्रेजों को न केवल भारतीय समाज के ज्ञान की जरूरत थी। बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण के रूपों को भी जन्म देना था जो औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा बेहतर ढंग से शासित हो सकता हो। केंद्रीय समस्याएं जो सामने आईं और उन्हें समझा जाना था कि एक राजनीतिक-सैन्य प्रणाली कैसे विकसित की जाए, जो भारतीय हाथों में सरकार के दैनिक कामकाज को आसान बनायें और फिर भी भारतीय विषयों पर निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए एक सफल कार्यप्रणाली भी बनाये। भारत पर अध्ययन का जोर इस बात पर था कि भारत को बेहतर तरीके से कैसे शासित किया जाए। नियंत्रण और आदेश का पालन करने के लिए उन्हें की औपनिवेशिक परियोजना के लिए भारतीय भाषाओं का ब्रिटिश अध्ययन महत्वपूर्ण था।

बोध प्रश्न 2

- 1) ब्रिटिश समाज की तुलना में भारतीय समाज के लिए मिशनरी परिप्रेक्ष्य उनके अनुसार अनिवार्य रूप से असम्मानित था। इस तरह के अधःपतन के पीछे मुख्य कारण धार्मिक व्यवस्था में निहित था जो भारतीय संस्कृति का आधार है और एकमात्र तरीका जो भारतीय अपनी स्थिति से उबर सकते हैं वह मिशनरी अभियानों के माध्यम से होगा जो भारतीय आबादी को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देगा। (बाइबल के अनुवाद की आवश्यकता के रूप में) भारतीय भाषाओं के सामाजिक-भाषिक अध्ययन की ओर अग्रसर किया। मिशनरियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में भी मदद की, जंगलों में आदिवासियों के बीच, दूर के इलाकों में काम करने के लिए गए, विशेष रूप से एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में ईसाई धर्म की पेशकश करने के लिए कमजोर और गरीबों के लिए उत्साह के साथ काम किया, उन लोगों के लिए जो पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर पर थे और जाति व्यवस्था में शोषित थे।
- 2) हालांकि उनके विश्लेषण में, जबकि मिशनरियों ने भारतविदों (भारतीय समाज के विद्वानों) और बाद में ओरिएंटलिस्ट (पूर्वी दुनिया के विद्वानों) के साथ भारतीय समाज के केंद्रीय सिद्धांतों के बारे में सहमति व्यक्त की, दोनों ने राजनीतिक संगठन, भूमिकार्य काल के तथ्यों को ठीक करने का प्रयास नहीं किया, वास्तविक कानूनी प्रणाली और समाज की पारम्परिक संरचना को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया।

अंतर मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति के उनके मूल्यांकन में है। जबकि ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिस्ट में एक प्राचीन भारतीय सभ्यता की अत्यधिक प्रशंसा थी और उस आदर्श से भारतीय समाज के पतन से दुखी थे, मिशनरियों का मानना था कि भारतीयों का कोई गौरवशाली अतीत नहीं था और यह हमेशा उच्छृंखलता और बेहूदगीयों से भरा रहा है। इंडोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्ट मिशनरियों जो उच्च वर्ग की पृष्ठभूमि और बेहतर शिक्षा से जुड़े थे, के विपरीत मिशनरी, विशेष रूप से बैपटिस्ट ब्रिटिश समाज के निचले पायदान से आए थे, जो स्वयं को और निश्चित रूप से भारतीय समाज दोनों को सुधारने के लिए एक उत्साह के साथ आए थे। वे इंडोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्ट जिन्होंने भारतीय पारंपरिक प्रणाली के लिए एक निश्चित सम्मान रखा के विपरीत ईसाई धर्म के पक्ष में सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए दृढ़ थे।

- 1) प्रशासनिक दृष्टिकोण प्रभावी औपनिवेशिक प्रशासन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में जातियों और जनजातियों के बारे में वर्गीकृत विवरणों के साथ सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को परिचित करना था। प्रशासकों द्वारा भारतीय समाज की व्याख्या, ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित और उपयोगितावादी तर्कवाद द्वारा प्रेरित, अधिक व्यावहारिक और अधिक महत्वपूर्ण तथ्य था, क्योंकि उनका उद्देश्य इन संसाधनों का दोहन करके इसे समझना था। भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विद्वानों के प्रशासकों ने नियुक्त किया, उदाहरण के लिए, पूर्वी भारत में रिस्ले, डाल्टन और ओ, मैले, उत्तरी भारत में क्रुक ने भारत की जनजातियों और जातियों के बारे में विश्वकोश लिखा, जो आज भारतीय जीवन के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करते हैं और संबंधित क्षेत्रों के लोगों की संस्कृति के बारे में भी। सर विलियम जोन्स ने संस्कृत और इंडोलॉजी का अध्ययन शुरू किया और 1787 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के लिए भी वे काफी प्रसिद्ध हैं। 1794 में जोन्स द्वारा मनु के कानून का अनुवाद किया गया था।
- 2) चार्ल्स मेटकाफ, ने भारतीयों को "गाँव समुदायों" में रहने वालों के रूप में वर्णित किया, जो "छोटे एक गणराज्य हैं", जिनके पास वे सब कुछ हैं जो वे अपने भीतर चाहते हैं, और लगभग किसी भी विदेशी संबंधों से स्वतंत्र हैं। ब्रिटिशों ने ब्रिटिश अतीत जीवन जीने के लिए रोमांटिक, आदर्शवादी और विकासवादी मिथक का समर्थन किया - 'खुश किसानों से घिरे देश के रूप में'। 'जाति 'और' गाँव 'के दृष्टिकोण ने मिलकर ब्रिटिश शासकों को राजस्व कानूनों को बनाने में मदद की, जमींदारों के वर्ग का निर्माण किया और व्यावसायिक कृषि प्रथाओं को भी लागू किया। भारत के गाँवों पर मेन और बाडेन-पॉवेल के कई शोध अध्ययनों के बावजूद, गाँव के बारे में श्रेणीगत और वैचारिक दृष्टिकोण उस स्तर पर स्थिर रखा गया जब यह मानव समाज के विकासवादी प्रक्रिया में एक 'प्रकार' था जिसने भारत के भीतर संरचना और संस्कृति दोनों के संदर्भ में गाँव के स्तर के संघर्ष, गाँवों की क्षेत्रीय विविधताओं आदि पर चर्चा की।

2.9 शब्दावली

मिशनरी विचार : यह विचार 18वीं शताब्दी में शुरुआती मिशनरियों के लेखन के माध्यम से विकसित हुआ।

सजातीय विवाह : किसी एक समुदाय/समूह/जाति/जनजाति के भीतर सजातीय विवाह

सहभोज: एक साथ भोजन करना

प्रशासनिक दृष्टिकोण : इन अध्ययनों का उद्देश्य प्रभावी औपनिवेशिक प्रशासन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में जातियों और जनजातियों के बारे में वर्गीकृत विवरणों के साथ सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को परिचित करना था।

उपयोगितावादी तर्कवाद : दर्शन की एक प्रणाली के रूप में तर्क और तर्कसंगतता का व्यावहारिक उपयोग।

इकाई 3 राष्ट्रवादी विमर्श*

इकाई की रूपरेखा

- 3.0 उद्देश्य
- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा
- 3.3 भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रवाद: कुछ प्रमुख विमर्श
 - 3.3.1 ए.आर. देसाई के राष्ट्रवाद पर विचार
 - 3.3.2 राष्ट्रवाद पर पार्थ चटर्जी के विचार
 - 3.3.3 एम. चौधरी के राष्ट्रवाद पर विचार
- 3.4 स्वतंत्र भारत और उसके बाद की चुनौतियाँ
- 3.5 सारांश
- 3.6 संदर्भ
- 3.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

इस इकाई के माध्यम से पढ़ने के बाद, आप कर सकेंगे:

- राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा पर चर्चा;
- औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक भारत दोनों में राष्ट्रवादी विमर्श की व्याख्या;
- भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रमुख भारतीय विद्वानों के विचारों की चर्चा; तथा
- उत्तर-उपनिवेशवाद के राष्ट्रीयता विमर्श का विश्लेषण।

3.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में, हमने औपनिवेशिक विमर्श पर चर्चा की, जिसमें हमने यह समझाने की कोशिश की कि ब्रिटिश भारतीय समाज को किस दृष्टि से देखते थे। आपने प्रशासनिक दृष्टिकोण और मिशनरी दृष्टिकोणों के बारे में जाना।

यह इकाई भारतीय समाज को समझने के लिए राष्ट्रवादी वृत्तान्त पर चर्चा करेगी। शुरू करने के लिए, हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा और इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा, हम राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य के माध्यम से भारतीय समाज को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे। हम औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय राष्ट्र और भारतीय राष्ट्रवाद पर हुई विभिन्न चर्चाओं की व्याख्या करेंगे। अंत में, हम चर्चा करेंगे राष्ट्रवाद और भारत की स्वतंत्रता के बाद की स्थिति पर, और विशेष रूप से पृजाति, जाति, क्षेत्र आदि की तर्ज पर राष्ट्रवादी आंदोलन पर चर्चा करेंगे।

* डॉ. प्रफुल कुमार

3.2 राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा

एक राष्ट्र की अवधारणा 19वीं शताब्दी की उपज थी, जो पश्चिमी देशों से भारत में सामने आई और बाद में यूरोप के अन्य उपनिवेशों यानी एशिया, अफ्रीका आदि में फैल गई। एक राष्ट्र को ऐसे लोगों के समूहों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामान्य क्षेत्र, इतिहास, भाषा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि आदि साझा करते हैं, एक राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि यह हमेशा संप्रभु/स्वतंत्र/स्वायत्त होते हैं। इसलिए, राष्ट्र की शास्त्रीय समझ में, एक राष्ट्र को तभी मान्यता दी जाती है जब वह स्वतंत्र होता है। उसी समय, संप्रभु क्षेत्र में सदस्य एक समान इतिहास, भाषा, संस्कृति आदि साझा करते हैं। यह इतिहासकारों का विचार है कि आधुनिक अर्थों में राष्ट्रवाद औद्योगिक पूंजीवाद या प्रिंट पूंजीवाद के विकास के साथ उभरा और तब इसका निरंतर अस्तित्व कई कारकों की वजह से था। इन कारकों की वजह थी, विविधता - भाषा, जातीयता या धर्म के आधार पर या राज्यों और कल्पना समुदायों के बीच प्रतिद्वंद्विता और प्रतियोगिता के आधार पर समुदाय की धारणाएं। जैसे 19वीं सदी में या 20वीं सदी के 1950 के दशक तक राष्ट्र और राज्य (Nation of State) कई बार पर्यायवाची थे। तात्पर्य यह है कि एक संप्रभु राज्य बनाने के लिए एक राष्ट्र होना चाहिए या इसके विपरीत केवल एक राष्ट्र का गठन तभी किया जा सकता है यदि यह एक संप्रभु राज्य है। ऐसी शास्त्रीय परिभाषा है कि एक राष्ट्र को ही शासन करना चाहिए।

राष्ट्र की सबसे स्वीकृत शास्त्रीय परिभाषा स्टालिन ने दी थी, जिन्होंने राष्ट्र को एक "ऐतिहासिक रूप से विकसित, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक जीवन और संस्कृति के समुदाय में प्रकट मनोवैज्ञानिक दृष्टि" के रूप में परिभाषित किया था (स्टालिन 1991: 6)।

राष्ट्र की परिभाषा आसान नहीं है। यह कठिन और विवादास्पद दोनों है। राष्ट्र को परिभाषित करने के किसी भी प्रयास के साथ मुख्य समस्या यह है कि एक समय में, हमें बड़ी संख्या में ऐसे राष्ट्र मिल जाएंगे जो उस परिभाषा के अनुरूप नहीं हैं। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रों की वास्तविक दुनिया इतनी विविधतापूर्ण है (उनकी समानता के बावजूद) कि कोई भी एक परिभाषा सभी को शामिल करने की उम्मीद नहीं कर सकती है। यह आंशिक रूप से इस कारण से है कि विद्वानों ने आम तौर पर सभी स्थितियों के लिए लागू राष्ट्र की एक सार्वभौमिक परिभाषा प्रदान करने से परहेज किया है। उन्होंने विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन करना आसान पाया है। विशिष्ट अनुभवों के आधार पर कुछ व्यापक सिद्धांतों को अमूर्त करना अधिक कठिन हो गया है। अर्नेस्ट गेलनर, (उद्धृत) इस विषय पर एक और महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हैं, जिन्होंने दो विशेषताओं की पहचान की जो संभवतः सामान्य परिभाषा का हिस्सा बन सकती हैं:

क) संस्कृति और

ख) संकल्प

लेकिन वह खुद जानता था कि वे अपर्याप्त हैं और वास्तव में दोनों विशेषताएँ सभी प्रकार के राष्ट्रों की सही पहचान नहीं कर पातीं। वे उन्हें फिर से उद्धृत करते हैं:

"फिर क्या यह आकस्मिक है, लेकिन हमारे समय में राष्ट्र के विचार सार्वभौमिक और प्रामाणिक हैं? दो बहुत ही कामचलाऊ चर्चा, अस्थायी परिभाषाओं की चर्चा इस कठिन अवधारणा को इंगित करने में मदद करेगी।

1) दो व्यक्ति एक ही राष्ट्र के हैं यदि और केवल तभी जब वे एक ही संस्कृति को साझा करते हैं, जहां संस्कृति का अर्थ विचारों और संकेतों और संघों और व्यवहार और संचार के तरीके से हो।

2) दो व्यक्ति एक ही राष्ट्र के हैं किन्तु और केवल तभी जब वे एक दूसरे को एक ही राष्ट्र का वासी मानते हैं और पहचानते हैं।

दूसरे शब्दों में, राष्ट्र मनुष्य को बनाते हैं। राष्ट्र पुरुषों के विश्वास, निष्ठा और एकजुटता के गुण हैं। व्यक्तियों की एक मात्र श्रेणी (कहते हैं, किसी दिए गए क्षेत्र के रहने वाले, या किसी भाषा के बोलने वाले, उदाहरण के लिए) एक ऐसा राष्ट्र बन जाता है, यदि और जब श्रेणी के सदस्य अपने साझा किए गए पुण्य के फलस्वरूप एक-दूसरे को कुछ पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों को दृढ़ता से पहचानते हैं इसकी सदस्यता इनमें से प्रत्येक की अन्तरिम परिभाषा, सांस्कृतिक और स्वैच्छिक है, जिसमें कुछ योग्यता है। उनमें से प्रत्येक एक तत्व को बाहर निकालता है जो राष्ट्रवाद की समझ में वास्तविक महत्व रखता है। लेकिन इसमें से कोई तथ्य पर्याप्त नहीं है। संस्कृति की परिभाषा, पहली परिभाषा की पूर्वमान्यता के अनुसार, मानक अर्थ के बजाय मानवशास्त्रीय परिभाषा में, असंतोषजनक हैं। औपचारिक परिभाषा के मार्ग में बहुत अधिक प्रयास किए बिना इस शब्द का उपयोग करके (राष्ट्र) इस समस्या का संभावित उत्तम अर्थ सबसे अच्छा है। "(1983, पृष्ठ 7)।

राष्ट्रवाद का आधुनिक विचार 19वीं शताब्दी के आरंभ में पश्चिमी यूरोप से आया, जिसमें तीन किस्में थीं, जिन्होंने इसकी रचना की:

- 1) राजनीतिक आत्मनिर्णय के उदार संकल्पना के रूप में ज्ञानोदय, (रूसो, जेम्स मिल्ल्स और अन्य)
- 2) समान नागरिकों के समुदाय का फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचार, और
- 3) इतिहास, परंपरा और संस्कृति द्वारा गठित लोगों की जर्मन अवधारणा।

अंतिम प्रक्रिया-उत्पाद के रूप में, राष्ट्रवाद इस प्रकार स्वतंत्रता, समानता और इतिहास और संस्कृति के सामूहिक बंटवारे के सिद्धांतों से बंधा हुआ था। '(डायस्पोरा और ट्रांसनैशनल समुदाय, MSOE- 002 पुस्तक 2 पृ 148)।

दूसरी ओर राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति व्यक्ति की निष्ठा और अपनेपन का भाव है। अपनेपन, या निष्ठा का ऐसा भाव उसके जन्म, उसकी भाषा, संस्कृति आदि के कारण आता है।

अर्नेस्ट गेलनर ने अपनी पुस्तक के शुरुआती अनुच्छेद में इन शब्दों को परिभाषित किया है:

"राष्ट्रवाद मुख्य रूप से एक राजनीतिक सिद्धांत है, जो मानता है कि राजनीतिक इकाई और राष्ट्रीय इकाई के अनुरूप होनी चाहिए। एक भावना के रूप में, या एक आंदोलन के रूप में राष्ट्रवाद, इस सिद्धांत के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। राष्ट्रवादी भावना, सिद्धांत के उल्लंघन से पैदा हुए क्रोध की भावना है, या इसकी पूर्ति से उत्पन्न संतुष्टि की भावना है। एक राष्ट्रवादी आंदोलन इस तरह की भावना से प्रेरित होता है "(अर्नेस्ट गेलनर 1983: 1)।

बॉक्स 3.0

राष्ट्रवादी विचारधारा के मुख्य विषय :

- 1) मानवता स्वाभाविक रूप से राष्ट्रों में विभाजित है।
- 2) प्रत्येक राष्ट्र का अपना विशिष्ट चरित्र है।
- 3) समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत राष्ट्र, और संपूर्ण सामूहिकता है।

- 4) स्वतंत्रता और आत्म प्राप्ति के लिए, मनुष्यों को एक राष्ट्र के साथ पहचान करनी चाहिए।
- 5) राष्ट्र केवल अपने राज्यों में ही पूर्ण हो सकते हैं।
- 6) राष्ट्र के प्रति वफादारी अन्य सभी वफादारियों से सर्वोपरि है।
- 7) वैश्विक स्वतंत्रता और सामंजस्य की प्रमुख शर्त राष्ट्र-राज्य की मजबूती है। (संदर्भ) एडम स्मिथ

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

- 1) राष्ट्र की अवधारणा क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) राष्ट्रवाद के आधुनिक विचार के माध्यम से तीन गुण क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3.3 भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रवाद : कुछ प्रमुख विमर्श

औपनिवेशिक सत्ता के भारत में आने से पहले, क्षेत्र भारत को विभिन्न छोटे-बड़े रियासतों और राजवंशों में विभाजित किया गया था। धर्म, संस्कृति, भाषा और क्षेत्र के संदर्भ में इसकी विविधता के कारण यह व्यापक रूप से माना जाता था कि भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें एक सामान्य संस्कृति, भाषा या एक सामान्य इतिहास नहीं था, बल्कि इसमें बहुत अधिक विविधताएं थीं। भारत के राष्ट्रवाद 'में मदद करने वाले कारक:

- 1) अंग्रेजों ने उन विभिन्न खंडों को एक विलक्षण प्रशासनिक दायरे में लाये और साथ ही नौकरशाही, पश्चिमी शिक्षा, कानून, अदालत, संचार के साधन, प्रिंटिंग प्रेस आदि जैसे विभिन्न आधुनिक संस्थानों की शुरुआत की। (उन्होंने भारतीय समाज में बदलाव लाए, लेकिन इसके विपरीत इसने भारतीय लोगों के साथ-साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए औपनिवेशिक शक्ति की भी मदद की)।
- 2) तत्कालीन औपनिवेशिक-विरोधी आंदोलन के उदय ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन

के बाद, इसने आंदोलन को तेज किया और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकता के एक सूत्र में लाने के लिए प्रेरित किया।

- 3) उन्होंने उन विविधताओं को बांधने के लिए कुछ प्रतीकों का निर्माण किया जैसे कि आम भाषा (हिंदी), सामान्य ध्वज, राष्ट्रीय गीत/गान, आदि। इस प्रकार विविधता के बावजूद विविध वर्गों के बीच एक आम भावना पैदा की गई। इन्हें व्यापक रूप से विविधता में एकता के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, बाद में गांधी, नेहरू, पटेल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन को तेज करने के लिए भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन जैसे अहिंसा, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि में नए व्याख्यान जोड़े।
- 4) यूरोपीय राष्ट्रवाद के यूरोपीय मॉडल के विपरीत भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में, उपनिवेश विरोधी आंदोलन ने भी बड़ी भूमिका निभाई। कई विद्वानों का तर्क है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय से अधिक उपनिवेशवाद विरोधी था। यह संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर ला सका।

पिछले 200 -250 वर्षों के दौरान, भारतीय राष्ट्रवाद में कई बदलाव हुए हैं। औपनिवेशिक काल में, राष्ट्रवाद मूल रूप से उपनिवेशवाद-विरोधी था और स्वतंत्रता संग्राम के नेता सभी वर्गों को एक छत्र के नीचे ला सकते थे, हालांकि विभिन्न चरणों में प्रतियोगिताएं होती थीं। इस तरह की प्रतियोगिताएं दक्षिणपंथी हिंदू और मुस्लिम दोनों नेताओं से हुईं। जैसे, औपनिवेशिक काल में संस्कृति की रेखा में एक प्रकार का धार्मिक राष्ट्रवाद उभर कर सामने आया। इसके अलावा, दलितों और निचली जातियों के समूहों से भी विशेषकर अंबेडकर के नेतृत्व में संघर्ष हुआ। विशेष रूप से दलितों और छोटे राष्ट्रीयताओं के अनसुने मुद्दों को बाद में भारतीय राज्य के रूप में शामिल किया गया था, जिसका विरोध प्रतिरोध के रूप में किया गया था और इसका विरोध बड़े पैमाने पर जातीय आंदोलनों के रूप में किया जाता था। भारत में इस समय काफी संप्रदायिक मतभेदों का सामना करना पड़ा था।

औपनिवेशिक काल के बाद के भारत में विभिन्न उप-नागरिकों, क्षेत्रीय और जनजातीय आंदोलनों ने एक राष्ट्र के रूप में भारत के विचार या एक राष्ट्र के रूप में भारत को चुनौती दी। कई बार विभिन्न समूहों का राष्ट्रवादी विमर्श हमें क्षेत्रीय असमानता, विविधता आदि को समझने की गुंजाइश देता है। इसलिए, राष्ट्रीयता विमर्श औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रवाद के विभिन्न शास्त्रीय विचारों के अलावा, भारत में राष्ट्रवादी विमर्श को समझने के लिए कई अन्य चर्चाएं और व्याख्याएं हैं। उनमें ए. आर. देसाई, डी. डी. कोसांबी, पार्थ चटर्जी आदि ने भारतीय राष्ट्रवाद को समझने के लिए नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की मार्क्सवादी दृष्टिकोण से व्याख्या की जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया। भारतीय राष्ट्रवाद पर पार्थ चटर्जी की थीसिस बेनेडिक्ट एंडरसन के राष्ट्र और राष्ट्रवाद के विचार की आलोचना है और उन्होंने चर्चा की कि भारतीय राष्ट्रवाद का गठन राष्ट्र के पश्चिमी गठन से अलग था। यहां हम स्वतंत्र भारत में विभिन्न जातीय समूहों की राष्ट्रीयता आंदोलन को समझने के लिए पॉल ब्रास पर और औपनिवेशिक काल में राष्ट्रवाद को समझने के लिए ए. आर. देसाई और पार्थ चटर्जी पर चर्चा करेंगे।

- नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।
ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।
- 1) राष्ट्रीयता के निर्माण में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा ?

.....
.....
.....
.....
.....

3.3.1 ए.आर. देसाई और भारतीय राष्ट्रवाद

ए. आर. देसाई भारत के प्रमुख समाजशास्त्रियों में से एक थे। वह भारतीय समाज को समझने में विचार के मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भौतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करके भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हैं। उनकी पुस्तक "सोशल बैकग्राउंड ऑफ़ इंडियन नेशनलिज्म" (1946) औपनिवेशिक भारत की सामाजिक स्थितियों को समझने के लिए पथ-प्रदर्शक कार्यों में से एक थी। भारतीय राष्ट्रवाद में हालिया रुझान (1960) देसाई का एक और महत्वपूर्ण कार्य है।

देसाई ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए औपनिवेशिक, और बाद के औपनिवेशिक काल को देखा। भारत में पूर्व-औपनिवेशिक काल के दौरान सामंती वर्ग किसान वर्ग पर हावी था। यह सामंती वर्ग, जिनमें से कई मुस्लिम शासकों के अधीन थे, ने किसानों का शोषण किया।

भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि में देसाई (1946) ने औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज में संरचनात्मक परिवर्तनों की व्यापक समझ का विश्लेषण किया है। उन्होंने सामंतवाद, उसके परिवर्तनों और पूंजीवादी ताकतों के उदय के दौरान उत्पादन संबंधों की जांच की और आखिरकार इस तरह की सामाजिक परिस्थितियों में राष्ट्रवाद कैसे उभरा। देसाई ने विश्लेषण किया कि भारत में राष्ट्रवाद क्यों और कैसे उभरा और सामाजिक और भौतिक परिस्थितियाँ क्या थीं। देसाई ने विभिन्न कारकों को समझने की कोशिश की जिसके कारण दुनिया के विभिन्न कोनों में राष्ट्र निर्माण हुआ। उसके लिए विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद के विकास के बाद और संबंधित देश के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के साथ-साथ "राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं, और सामाजिक वर्गों के मनोवैज्ञानिक और आर्थिक लक्षणों के विशिष्ट चरित्र निर्धारित किए गए थे जो उन देशों में एक राष्ट्रीय सामाजिक अस्तित्व के लिए संघर्ष का मोहरा थे। प्रत्येक राष्ट्र इस प्रकार एक अनोखे तरीके से पैदा हुआ और इसी तरह पनपा था।"

देसाई ने राष्ट्रीय भावना की उत्तेजना को समझा, इसलिए उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में ऐसी भावनाएं प्रमुख हैं। सभी प्रकार के समकालीन आंदोलनों जैसे कि आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि राष्ट्रवाद की ऐसी भावनाओं से प्रेरित थे।

भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास की पड़ताल करते हुए, देसाई उपनिवेशवाद में उसकी जड़ में पाते हैं। उनका मानना है कि भारतीय समाज में विकसित कई व्यक्तिपरक और उद्देश्य

विचारों के कारण उन्होंने कार्यों और अंतर-क्रियाओं से भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण में मदद की। लेकिन, उनका तर्क है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया अपने आर्थिक और अन्य कारकों के कारण बहुत जटिल थी। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना काफी अनोखी थी। मध्यकालीन यूरोपीय समाजों और देशों के विपरीत भारतीय समाज का आर्थिक आधार अलग था। इसके अलावा, भौगोलिक, भाषा, सांस्कृतिक अंतर इस क्षेत्र को अद्वितीय और जटिल बनाते हैं। लेकिन इतने मतभेदों के बावजूद भारत में ब्रिटिश शासन ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास के लिए वे कारण प्रदान किये। ब्रिटिश शासन और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच संबंधों को देखने वाले देसाई का तर्क है "ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय लोगों की राजनीतिक अधीनता की वजह से अनेक अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए उन्नत किया ब्रिटिश राष्ट्र, भारतीय समाज की आर्थिक संरचना को मौलिक रूप से बदल दिया, एक विकेंद्रित (केंद्रीकृत) राज्य की स्थापना की, और आधुनिक शिक्षा, संचार के आधुनिक साधन और अन्य संस्थानों की शुरुआत की। इससे नए सामाजिक वर्गों का विकास हुआ और अपने आप में अद्वितीय नई सामाजिक शक्तियों का उदय हुआ। अपने स्वभाव से ये सामाजिक ताकतें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ संघर्ष में आ गईं और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास के लिए लक्षित (मकसद) शक्ति का आधार बन गईं"।

देसाई ने औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज के मूलभूत आर्थिक परिवर्तन का विश्लेषण किया है। उन्होंने माना कि आर्थिक परिवर्तन क्षेत्र की विविध आबादी को एकजुट करने के लिए आवश्यक सामग्री में से एक था। साथ ही उन्होंने भारतीय लोगों के एकीकरण की दिशा में योगदान देने और उनके बीच एक राष्ट्रवादी चेतना जगाने में आधुनिक परिवहन, नई शिक्षा, प्रेस, और अन्य कारकों की भूमिका को भी संबोधित किया।

देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को पाँच चरणों में वर्गीकृत किया:

1) पहला चरण

पहले चरण में, भारतीय राष्ट्रवाद का एक संकीर्ण सामाजिक आधार था। 19वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान शैक्षिक संस्थानों की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, जो नए शिक्षित भारतीयों का एक समूह पैदा कर सके थे, जिन्होंने पश्चिमी संस्कृति का अध्ययन किया और उन्होंने अपने लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी मूल्यों को आत्मसात किया। उन शिक्षित बुद्धिजीवियों ने भारतीय राष्ट्रवाद की पहली धारा बनाई। राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्र के विचार के पहले प्रतिपादक थे। उन्होंने इस विचार का अपने लोगों में प्रचार किया। विभिन्न भारतीयों ने धार्मिक सुधार आंदोलनों से समाज में बदलाव किया। शिक्षितों का विचार था कि "भारतीय समाज और धर्म को लोकतंत्र, तर्कवाद और राष्ट्रवाद के नए सिद्धांतों की भावना में बदल देना है। वास्तव में, ये आंदोलन भारतीय लोगों के एक वर्ग के बीच बढ़ती राष्ट्रीय लोकतांत्रिक चेतना की अभिव्यक्ति थे "(वही: 409)। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के साथ-साथ प्रशासन में भी भारतीयों का आवाज को शामिल करने की मांग की। 1885 तक पहला चरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ समाप्त हुआ।

2) दूसरा चरण

दूसरे चरण में लगभग 1885-1905 की अवधि शामिल थी। कांग्रेस को चलाने वाले उदारवादी बुद्धिजीवी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। इस अवधि के दौरान पश्चिमी शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ भारत और भारत के बाहर व्यापार के विकास के कारण एक नया व्यापारी वर्ग और शिक्षित अभिजात वर्ग भारत में विकसित हुआ। भारत में स्थापित आधुनिक औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप औद्योगिक वर्ग का विकास

हुआ। इस वर्ग ने ताकत हासिल करना शुरू कर दिया। यह वर्ग कांग्रेस के करीब हो गया जिसने "देश के औद्योगीकरण के कार्यक्रम को अपनाया और 1905 में स्वदेशी अभियान को सक्रिय रूप से संगठित किया"। इस चरण ने सेवाओं के भारतीयकरण के साथ-साथ कई भारतीयों को खुद को प्रशासनिक और राज्य मशीनरी के साथ जोड़ा। इस चरण में भारत में उग्रवाद का उदय भी हुआ।

3) तीसरा चरण

तीसरे चरण की पहचान 1905-1918 के बीच देसाई ने की। तीसरे चरण में उदारवादियों की जगह अतिवादियों (एक्स्ट्रेमिस्ट्स) ने ले ली। यह उग्रवाद और निम्न मध्यम वर्ग को शामिल करने का दौर था। यह चरमपंथी राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मविश्वास की भावना पैदा कर सका था। देसाई कहते हैं कि इस अवधि के दौरान नेताओं ने एक हिंदू दर्शन पर ऐसी चेतना को आधार देने का प्रयास किया। यह धर्मनिरपेक्ष भारत के चरित्र को कमजोर बना सकता था। उसी समय उच्च वर्ग के मुसलमानों ने भी राजनीतिक चेतना विकसित की और मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की।

4) चौथा चरण

चौथा चरण 1918 से शुरू होता है जब तक कि नागरिक आज्ञाकारिता आंदोलन (Civil Disobedience Movement) 1930-34 तक नहीं चलता। यह राष्ट्रवादी आंदोलन के विस्तार की अवधि थी, जो पहले मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग तक सीमित थी। देसाई कई कारकों को देखते हैं जो भारतीय जनता के बीच राष्ट्रीय जागृति लाते हैं। उनका मानना है, "युद्ध के बाद का आर्थिक संकट, सरकार के वादों के बारे में मोहभंग, और राज्य द्वारा बढ़ते दमन ने किसानों और मजदूर वर्ग सहित लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था और वे बहुत बुरी स्थिति में थे" (वही) : 412।

इसके अलावा, कई देशों के लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ-साथ रूस में समाजवादी क्रांति ने भारतीय जनता को प्रोत्साहित किया। उसी समय औद्योगिक विस्तार के कारण युद्ध के दौरान भारतीय पूंजीपति आर्थिक रूप से मजबूत हुए। कांग्रेस के स्वदेशी या बहिष्कार के नारे ने अंततः उन भारतीय पूंजीपतियों की मदद की जिन्होंने इस आंदोलन का आर्थिक सहारा दिया।

5) पांचवा चरण

भारतीय राष्ट्रवाद और भारत की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन के पांचवें चरण में 1934-39 की अवधि, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप का वर्ष है। यह चरण विभिन्न समूहों द्वारा गांधी की विचारधारा के साथ निराशा को दर्शाता है, विशेष रूप से कांग्रेस के अंदर विभिन्न समूहों का उदय हुआ। अहिंसा और स्वदेशी की गांधीवादी विचारधारा पर कई कांग्रेसियों ने अपना विश्वास खो दिया। सोशलिस्ट पार्टी ने मजदूरों और किसानों की समस्याओं के आधार पर खड़ा किया। अवसादग्रस्त वर्गों के उदय, असंतुष्टों ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। हम इस अवधि के दौरान मुस्लिम लीग का उदय भी देखते हैं।

इस प्रकार, देसाई ने भारतीय राष्ट्रीयता के एक मार्क्सवादी विश्लेषण को भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए प्रस्तुत किया।

बोध प्रश्न 3

ध्यान दें:

खाली जगह भरें

- अ) भारत में पूर्व-औपनिवेशिक काल के दौरान वर्ग किसानों के वर्ग पर हावी था।
- ब) देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को चरणों में वर्गीकृत किया।
- स) पहला चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ समाप्त हुआ।
- द) तीसरे चरण में उदारवादियों की जगह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

3.2.2 राष्ट्रवाद पर पार्थ चटर्जी का विचार

राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर बेनेडिक्ट एंडरसन के विचार राष्ट्र और राष्ट्रवाद के विमर्श में सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांतों में से एक हैं। उनकी पुस्तक इमेजिड कम्युनिटीज (Imagined Community) (1991) ने राष्ट्र और राष्ट्रवाद को समझने के लिए नए विचारों को प्रदान किया। एंडरसन का तर्क है कि राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय है जिसके बारे में कल्पना की जाती है। उसके लिए, राष्ट्र एक कल्पनाशील समुदाय होने के साथ-साथ एक सांस्कृतिक कलाकृति है "... एक कल्पना की गई राजनीतिक समुदाय - और दोनों के रूप में स्वाभाविक रूप से सीमित और संप्रभु है" (एंडरसन 1991, 6)। इसकी कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि "यहां तक कि सबसे छोटे राष्ट्र के सदस्य भी अपने अधिकांश साथी-सदस्यों को कभी नहीं जान पाएंगे, उनसे मिल सकते हैं, या यहां तक कि उनके बारे में भी सुन सकते हैं, फिर भी प्रत्येक के मन में एक साथ सम्प्रेषण की छवि रहती है"। इस प्रकार राष्ट्र एक अमूर्त घटना है जहाँ समुदाय के सदस्य खुद को एक राष्ट्र के रूप में कल्पना करते हैं। यह सीमित भी है क्योंकि "राष्ट्र यहां तक कि उनमें से सबसे बड़ा राष्ट्र भी शायद एक अरब से भी ज्यादा जीवित मनुष्यों को शामिल करता है।

एंडरसन ने पश्चिमी देशों (यूरोप) में राष्ट्र के विचार के विकास की जांच की। वह कहते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रीय स्थितियों ने किसी घटना के गठन में मदद की। ऐसा ही एक कारक प्रिंट मीडिया का पूंजीवाद था - यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का उदय हुआ। प्रिंट मीडिया पूंजीवाद को अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता के रूप में इस्तेमाल करता है। हालाँकि एक समूह की बोली जाने वाली भाषा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है, लेकिन लिखित भाषा एक-दूसरे के समान और पारस्परिक रूप से बोधगम्य होती है। इसलिए समाचार पत्र, विशेष रूप से किताबें और सामान्य रूप से मीडिया पूंजीवाद एक राष्ट्रीय कल्पना बना सकते हैं। (एक ही समय में मुद्रण प्रौद्योगिकी के ऐसे रूपों ने सभी कोनों की खबरें छापीं, जिनके लिए यह राष्ट्रीय कल्पना आसान हो गया और एक-दूसरे को समझना भी संभव हो गया। एंडरसन का तर्क है कि "इस प्रक्रिया में, वे धीरे-धीरे सैकड़ों सैकड़ों लोगों के बारे में जागरूक थे, यहां तक कि लाखों को, अपनी विशेष भाषा क्षेत्र में, और एक ही समय में उन सैकड़ों, हजारों या लाखों लोगों से संबंधित थे। ये साथी पाठक, जिनके साथ वे अपने धर्मनिरपेक्ष, विशेष रूप से प्रिंट, गठन के माध्यम से जुड़े थे। दृश्यमान, अदृश्य, राष्ट्रीय कल्पना समुदाय के भ्रूण थे "(वही ,44))।

भारत की समझ : प्रमुख विमर्श एंडरसन आगे तर्क देते हैं कि यूरोप के उपनिवेशों में, समान आधार पर विभिन्न राष्ट्रों का गठन किया गया था।

दूसरी ओर, पार्थ चटर्जी ने कल्पना समुदाय पर एंडरसन के दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के गठन के बारे में एक अलग समझ प्रस्तुत की। चटर्जी ने एंडरसन के विचार पर सवाल उठाया कि राष्ट्र यूरोप में विकसित एक 'मॉड्यूलर' रूप था और बाद में भारत और अन्य जैसे उपनिवेशों द्वारा अपनाया गया। ऐसी धारणा की समस्या यह है कि पश्चिम ने राष्ट्र के नाम पर कॉलोनियों की कल्पना करने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। चटर्जी ने सवाल किया कि अगर "बाकी दुनिया को यूरोप और अमेरिका द्वारा पहले से उपलब्ध कराए गए कुछ 'मॉड्यूलर' रूपों में से अपने कल्पित समुदाय को चुनना है, तो उनके पास कल्पना करने के लिए क्या है?" (चटर्जी 1993, 5)।

इस तरह की धारणाओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एशिया और अफ्रीका में यूरोप की उपनिवेश केवल आधुनिकता के निरंतर उपभोक्ता थे, उनके पास पहले से ही राष्ट्रवाद के पूर्व संस्करण उपलब्ध थे। अधिक स्पष्ट रूप से, राष्ट्र के संबंध में कल्पना भी हमेशा उपनिवेश होती है।

चटर्जी ने इस मुद्दे पर बहस करते हुए कहा कि एंडरसन ने आध्यात्मिकता यानि स्पीरिचुअल की अनदेखी की - आंतरिक डोमेन के अंदर का स्थान, जहां उन्होंने राष्ट्रवाद को समझने के लिए बाहरी मैटीरियल (Material) डोमेन पर बहुत जोर दिया। चटर्जी, इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रवाद के नए आयाम यानी आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रस्ताव रखते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक डोमेन को देखा, जो घरों में या समाज में भारत में उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की मूल विशेष

ता के रूप में संरक्षित था। यह आंतरिक डोमेन समाज के सांस्कृतिक मार्करों (प्रतीकों) को वहन करता है जो संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय कल्पना के लिए आवश्यक है। औपनिवेशिक बंगाल से भारतीय राष्ट्रवाद का विश्लेषण करने के लिए उदाहरणों को देते हुए उन्होंने भाषा, संस्कृति, नाटक, स्कूलों, परिवार, महिलाओं आदि का उदाहरण दिया और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका का वर्णन किया। भाषा पर चर्चा करने में चटर्जी ने एक राष्ट्रीय भाषा के विकास के लिए प्रिंट मीडिया पूंजीवाद के एंडरसन के विचार को स्वीकार किया। बंगाल में हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी और क्रिश्चियन मिशनरियों ने 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाली भाषा में पहली किताबें प्रकाशित की थीं, लेकिन बंगाल के पढ़े-लिखे कुलीन जो द्वि-भाषी थे, उन्होंने इसे एक परियोजना के रूप में लिया - बाद में बंगाली भाषा में और अधिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए एक सांस्कृतिक परियोजना तैयार की। चटर्जी कहते हैं, "अपनी मातृभाषा को आवश्यक भाषाई उपकरणों के साथ प्रदान करने के लिए ताकि वह "आधुनिकसंस्कृति" के लिए उपयुक्त भाषा बन सके। (वही, 7)। समाचार पत्र, पत्रिका प्रकाशित किए गए थे, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 19वीं शताब्दी में बंगाल में हुई थी। इसके अलावा, भाषा के मानक आकार देने के लिए साहित्यिक निकाय समाने आए। यह सब औपनिवेशिक राज्य के दायरे से बाहर हुआ। एक समूह की भाषा राष्ट्रीयता के गठन के लिए मूल डोमेन में से एक है। यह एक ऐसे समूह की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के रूप में भी कार्य करता है जहाँ औपनिवेशिक सत्ता की शायद ही कोई भूमिका थी। 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से बंगाली कुलीन लोगों ने स्कूलों की स्थापना शुरू कर दी। इसने राज्य बनने से पहले "उपयुक्त शैक्षिक साहित्य" का निर्माण किया। डोमेन के बाहर, राज्य के ये स्कूल नई भाषा और साहित्य को सामान्य बनाने और सामान्य करने के स्थल थे। चटर्जी एक अन्य आंतरिक डोमेन यानी परिवार के बारे

भी बात करते हैं। उसके लिए, परिवार ने राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की यूरोपीय धारणा और इसकी कई परंपराओं, धार्मिक प्रथाओं को बर्बर माना जाता था क्योंकि 19वीं और 20 वीं शताब्दी के दौरान यह काफी प्रभावी थी। विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रथाओं की उनके द्वारा आलोचना की गई जैसे कि सती प्रथा। हालाँकि, भारत में नए उभरे कुलीन लोग उन प्रथाओं को सुधारने के लिए यूरोपीय लोगों को बोझ देने के लिए तैयार नहीं थे। एक राष्ट्र के सदस्यों को सुधार करना चाहिए - उन्हें स्वयं एक राष्ट्र की समस्याओं को सुधारने का अधिकार है। राष्ट्र बाहरी लोगों को अपने समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष रूप से हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। इस तरह की धारणाएं सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए जीवित रख सकती हैं। चटर्जी ने सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में महिलाओं की भूमिका की भी जांच की। महिलाएं सांस्कृतिक परंपराओं की वाहक हैं। हालाँकि, इस तरह की प्रथाओं से एक नई पितृसत्ता का उदय हुआ, लेकिन इसने राष्ट्रीय कल्पना में मदद की। कुलीन लोग चाहते थे कि उनकी महिलाएँ नये युग की महिलाएँ बनें, लेकिन फिर भी पूरी तरह पश्चिम की महिलाओं की तरह नहीं।

इस प्रकार, कल्पना की गई समुदायों पर एंडरसन के तर्क की आलोचना करते हुए चटर्जी ने हमें भारतीय राष्ट्रवाद का एक नया मॉडल पेश किया, जिसमें कहा गया कि भारत में राष्ट्रीयता का आध्यात्मिक आधार था। कुछ ऐसे रूप थे जिनके लिए औपनिवेशिक काल में किसी राष्ट्र की कल्पना संभव थी।

3.3.3 एम.चौधरी के राष्ट्रीयता पर विचार

चौधरी (1999) तीन आयामों के माध्यम से भारत के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद में दिखता है, जहाँ उसने महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। वह जिन कारकों को धारण करता है, इस प्रकार है :

- 1) "यह अपने आर्थिक पहलुओं में औपनिवेशिकता के एक अच्छी तरह से विकसित आलोचना पर आधारित था और एक आर्थिक विकास के लिए अग्रणी कार्यक्रम पर आधारित था" (चंद्राल 999: 17)। आर्थिक आत्मनिर्भरता, संप्रभुता, इक्विटी के साथ विकास भारतीय राष्ट्रवाद की बहुत पहचान का हिस्सा थे।
- 2) यह आंदोलन राजनीतिक लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध था, जिसे राष्ट्र निर्माण के कलंक के रूप में देखा जाता था (चन्द्र: वही)। राष्ट्रीय आंदोलन और फिर स्वतंत्र राज्य की दौड़ में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी महत्वपूर्ण थी।
- 3) भारतीय राष्ट्रवाद भी उपनिवेशवाद का एक 'सांस्कृतिक समालोचक और राष्ट्रीय संस्कृति' का दावेदार था। इस दावे में 'भारतीय नारीत्व' की छवि महत्वपूर्ण थी। जैसा कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद कुछ प्रकार की संस्कृति और परंपरा की मांग करते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह खुद को अपने समूह से जोड़ सकते हैं। जैसा कि चटर्जी भारतीय राष्ट्रवाद के मामले में तर्क देते हैं, कि भारतीय अभिजात वर्ग नहीं चाहता था कि बाहरी लोग आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करें जो कि संस्कृति का हिस्सा था और महिलाएं काफी हद तक इसकी संरक्षक थीं। यदि किसी सुधार की आवश्यकता है तो यह राष्ट्र द्वारा ही किया जाएगा न कि बाहरी लोगों द्वारा।

- नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें
ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें
- 1) पार्थ चटर्जी के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद अलग कैसे था ?

.....
.....
.....
.....
.....

3.4 स्वतंत्र भारत और उसके बाद की चुनौतियाँ

स्वतंत्र भारत के बाद, एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत के विचार को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न उप-राष्ट्रीय, जातीयता आंदोलनों के रूप में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आजादी के शुरुआती वर्षों में गंभीर आंदोलन द्रविड़ आंदोलन और नागाओं के बीच आंदोलन थे। वे एक स्वायत्त नागालैंड चाहते थे। स्वतंत्र खालिस्तान और कश्मीर के लिए आंदोलन हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में ये विभिन्न प्रकार के पहचान आंदोलन सामने आए, और इन्हें भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति और जनजाति के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। भारतीय घटक राज्यों को स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था। हालाँकि, अधिक राज्यों के निर्माण के लिए नई मांगें आने लगीं। इसी तरह, देश के कई हिस्सों में आदिवासी आंदोलन अलग-अलग समय पर अलग-अलग राज्य में अपनी स्वायत्तता के लिए भी हुए। उनमें से, विभिन्न जातीय समूहों के पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन और पश्चिम बंगाल के गोरखाओं के आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया।

बोध प्रश्न 5

- 2) भारतीय राष्ट्र के लिए विभिन्न चुनौतियाँ क्या हैं?

.....
.....
.....
.....
.....

3.5 सारांश

हमने औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद के कुछ बिंदुओं के साथ-साथ औपनिवेशिक काल के बाद के जातीयता और राष्ट्रीयता से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा की है। भारतीय समाज की गतिशीलता को समझने के लिए राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। वर्तमान समय के संदर्भ में भी विभिन्न उप-राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, आदिवासी और जातीय आंदोलनों

का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय विमर्श को समझना आवश्यक है। हमने भारत में राष्ट्रवाद पर ए. आर. देसाई, पार्थ चटर्जी और मैत्रेयी चौधरी जैसे विभिन्न विद्वानों द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछ प्रमुख विषयों पर व्याख्या की है। हमने बेनेट एंडरसन के इमेजिंड कम्युनिटी 'की अवधारणा और राष्ट्र की अवधारणा पर भी चर्चा की।

3.6 संदर्भ

एंडरसन, बेनेडिक्ट, 1991. इमेजिंड कम्युनिटीज़. रिप्लेक्संस ऑन द ओरिजिंस एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज़्म. लंदन: वरसो

ब्रास, पॉल आर. 1991. एथिसिटी अंड नेशनलिज़्म: थियरी अंड कम्पेरिजन. न्यू डेलही: सेज पब्लिकेशन

चटर्जी, पार्था. 1993. नेशन एंड इट्स फ्रग्मेंट्स: कोलोनियल अंड पोस्ट कोलोनियल हिस्टोरिज़. न्यू जर्सी: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस.

चौधरी, मैत्रेयी. 1999. " जेंडर इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशन- स्टेट". सोसिओलोजिकल बुलेटिन. वोल 48. नं). 113-133.

देसाई, ए. आर. 2000. सोसल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म. न्यू डेलही: पोपुलर प्रकाशन.

गेलनर, अर्नेस्ट. 1983. नेशंस एंड नेशनलिज़्म, इथका अंड लंदन: कोरनेल यूनिवर्सिटी प्रेस.

मुखर्जी, पार्था एन. 1994. " द इंडियन स्टेट इन क्राइसिस? नेशनलिज़्म अंड नेशन बिल्डिंग". सोसिओलोजिकल बुलेटिन, वोल 43, नं 1 (मार्च 1994), पृ. 21 - 49.

ओमवेत, गेल. 1994. "रिकन्स्ट्रक्टिंग द मेथोडोलोजी ऑफ एक्सप्लोइटेशन : कास्ट, क्लास अंड जेंडर एज़ कैटेगोरी ऑफ एनालिसिस इन पोस्ट कोलोनियल सोसायटीज़", अण्डरस्टैंडिंग द पोस्ट कोलोनियल वर्ल्ड: थियरी अंड मेथड. नीरा चंडोक (एड). न्यू डेलही: स्टर्लिंग पब्लिकेशन.

स्टेलिन, जोसेफ. 1991. मार्क्सइज़्म एंड नेशनल एंड कोलोनियल क्वेश्चन. न्यू डेलही. कनिष्क पब्लिशिंग हाउस.

डियास्पेरा अंड ट्रांस नेशनल कम्युनिटीज़ 2010 , MSOE-002, बुक 2 इग्नू, न्यू डेलही.

नेशन एंड नेशनलिज़्म 2018, MHI-09- B1E. पृ. 65.

3.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

- 1) स्टालिन ने राष्ट्र को एक "ऐतिहासिक रूप से विकसित, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक जीवन और संस्कृति के समुदाय में प्रकट मनोवैज्ञानिक मेकअप" के रूप में परिभाषित किया।
- 2) 19वीं सदी की शुरुआत में आधुनिक राष्ट्रवाद का आधुनिक विचार पश्चिमी यूरोप के तीन गुणों का मेल था:
 - क) ज्ञानोदय
 - ख) समान नागरिकों के समुदाय का फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचार, और
 - ग) इतिहास, परंपरा और संस्कृति द्वारा गठित लोगों की जर्मन अवधारणा।

भारत की समझ : प्रमुख विमर्श बोध प्रश्न 2

- 1) भारत को राष्ट्र बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि भारत विभिन्न रियासतों और राजवंशों में विभाजित था। धर्म, संस्कृति, भाषा और क्षेत्र के संदर्भ में इसकी विविधता के कारण यह व्यापक रूप से माना जाता था और यह धारणा थी कि भारत एक राष्ट्र नहीं बना सकता है क्योंकि इसमें एक सामान्य संस्कृति, भाषा या एक सामान्य इतिहास नहीं था।

बोध प्रश्न 3

- 1) रिक्त स्थान भरें
 - अ) सामंती
 - ब) पांच
 - स) 1885 में
 - द) अतिवादी

बोध प्रश्न 4

- 1) भारत में राष्ट्रवाद पश्चिमी राष्ट्रवाद से अलग था क्योंकि यह आध्यात्मिकता के आधार पर था।

बोध प्रश्न 5

- 2) स्वतंत्रता के बाद भारत को जिन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वे थे कि स्वतंत्रता के बाद के समय में विभिन्न प्रकार के पहचान आंदोलन सामने आए और जो भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति और जनजाति की तर्ज पर विभाजित किए जा सकते हैं।

इकाई 4 सबाल्टर्न (उपाश्रित) विमर्श*

इकाई की रूपरेखा

- 4.0 उद्देश्य
- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उपाश्रित: अवधारणा
 - 4.2.1 रणजीत गुहा और सबाल्टर्न स्टडीज
 - 4.2.2 डेविड हार्डमैन का देवी आंदोलन का अध्ययन
 - 4.2.3 उपाश्रित के रूप में दलित: बी.आर. अम्बेडकर
- 4.3 सारांश
- 4.4 संदर्भ
- 4.5 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के माध्यम से, आप निम्न कार्य कर सकेंगे:

- भारत में उपाश्रित के विचार पर चर्चा करेंगे;
- उपाश्रित दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से, औपनिवेशिक उप-लेखन और जाति पर अंबेडकर के विचारों और उनके जाति-विरोधी आंदोलन के बारे में बता पाएंगे; और
- उपाश्रित अध्ययन पर रणजीत गुहा और हार्डिमन के काम का मूल्यांकन कर सकेंगे।

4.1 प्रस्तावना

पिछली इकाइयों में राष्ट्रवादी विमर्श पाठ में भारत को समझने और इसके प्रमुख विमर्शों पर हमने चर्चा की है, पिछली इकाइयों में हमने भारतीय समाज पर अलग-अलग दृष्टिकोण पर चर्चा की है। जैसे हमने समझाया –

- 1) **इंडोलॉजिकल डिस्कोर्स:** भारतीय समाज का अपने शास्त्रीय ग्रंथों और साहित्य के माध्यम से अध्ययन।
- 2) **औपनिवेशिक प्रवचन:** ब्रिटिश उपनिवेशवादियों (मिशनरियों और प्रशासकों) द्वारा भारतीय समाज का अध्ययन विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए राष्ट्रवादी आंदोलन पर अलग-अलग दृष्टिकोण।

वर्तमान इकाई, सबाल्टर्नयानि उपाश्रित दृष्टिकोण पर चर्चा करेगी और भारत के समाजशास्त्र का आलोचनात्मक आकलन करेगी और इतिहास के प्रमुख लेखन में सीमान्तों की आवाज (किसानों/ आदिवासियों/ अनुसूचित जातियों) की अनुपस्थिति का आकलन करेगी। प्रारंभ में हम उपाश्रित की अवधारणा पर चर्चा करेंगे, जिसे इतालवी विद्वान एंटोनियो ग्राम्स्की द्वारा गढ़ा गया है। यह शब्द औपनिवेशिक अध्ययन के विकास के साथ बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया, खासकर जब इतिहास का एक नया चलन दक्षिण एशिया में किसानों के विद्रोह और आदिवासी विद्रोह के इतिहास को लिखने में शुरू हुआ। विद्वानों के एक समूह ने एक

*प्रफुल कुमार नाथ

नया चलन शुरू किया, जैसे कि रणजीत गुहा, डेविड हार्डमैन, पार्थ चटर्जी, शाहिद अमीन, ज्ञानेंद्रपांडे, डेविड अर्नोल्ड, सुमित सरकार, दिपेश चक्रवर्ती और अन्य। इन कुछ विद्वानों के साथ-साथ अम्बेडकर की भूमिका की भी चर्चा की जाएगी क्योंकि उन्होंने भारत में दलितों की मुक्ति, उत्थान और मुक्ति के लिए काम किया।

4.2 उपाश्रित : अवधारणा

एंटोनियो ग्राम्स्की द्वारा 'सबाल्टर्न' शब्द गढ़ा गया था। शुरू में इसका व्यापक रूप से सेना में निम्न अंडर रैंक को निरूपित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आजकल, सबअल्टर्न (उपाश्रित) शब्द का अर्थ है कि उसके विभिन्न गुणों जैसे कि आर्थिक स्थिति, जाति, जातीयता, लिंग, जाति, यौन उन्मुखता से अंडर (निम्न) श्रेणी के लोग हैं और वे लोग इस तरह से हाशिए पर हैं। इस प्रकार सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य समाज को नीचे से समझने का तरीका है। एक स्तरीकृत समाज में विभिन्न कारणों से हाशिए पर रहे लोग ज्ञान का उत्पादन करते हैं और उनकी खुद की राजनीति होती है। हालांकि इतिहास और अध्ययन का प्रमुख इतिहासलेखन या लेखन उन्हें अपनी चिंताओं से बाहर रखता है। सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य उन लोगों में दिखता है जो उपेक्षित और हाशिए पर हैं और कुलीन परिप्रेक्ष्य के साथ इसके विपरीत हैं।

इतालवी नव-मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्स्की ने हाशिए के लोगों को संकेतित करने के लिए अपनी जेल नोटबुक में सबाल्टर्न की अवधारणा शुरू की। सामान्य तौर पर, सबाल्टर्न का तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो अवर श्रेणी के हैं, लेकिन, ग्राम्स्की अपने सामान्य अर्थ की तुलना में बहुत व्यापक अर्थों में इस शब्द का उपयोग करते हैं। सबाल्टर्न के अनुसार, उनका मतलब सभी प्रकार के गैर-विषम लोगों से था, जो एक वर्ग विभाजित समाज में शक्तिशाली और उच्च वर्ग की स्थिति प्राप्त नहीं करपाते थे। जैसे, उपाश्रित का तात्पर्य ऐसे समूह या व्यक्तियों से है जो सत्ता संरचना से बाहर हैं। उन्हें प्रमुख सत्ता संरचनाओं द्वारा उपाश्रित या अधीन बनाया जाता है और वे प्रमुख शक्ति संबंधों के तहत पीड़ित होते हैं।

उपाश्रित शब्द लोकप्रिय शैक्षिक बहस में तब आया जब विद्वानों के एक समूह ने आदिवासी आंदोलन और औपनिवेशिक भारत के किसान आंदोलन और विद्रोहियों पर सबाल्टर्न स्टडीज़ शीर्षक के तहत निबंध और संस्करणों की श्रृंखला शुरू की। यह स्पष्ट है कि मुख्यधारा के राष्ट्रवादी आंदोलन के अलावा औपनिवेशिक सत्ता को भारत में विभिन्न जनजातीय विद्रोह और किसानों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इस तरह के प्रतिरोध और आंदोलनों को मुख्यधारा के इतिहासलेखन या इतिहास लेखन के अध्ययन द्वारा नजर अंदाज कर दिया गया था।

बॉक्स 4.0 : एंटोनियो ग्राम्स्की

एंटोनियो ग्राम्स्की एक इतालवी नव-मार्क्सवादी थे जिन्होंने मार्क्सवाद को फिर से परिभाषित किया, विशेष रूप से आर्थिक नियतिवाद जैसे पारंपरिक मार्क्सवाद के विचारों के माध्यम से। इटली के ट्यूरिन में अपने उच्च अध्ययन के दौरान, वह इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों के संपर्क में आए। ग्राम्स्की इतालवी सोशलिस्ट के सक्रिय सदस्य बन गए और अपने पत्रकारिता कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने मार्क्सवाद, क्रांति, पेरिस कम्यून, फ्रांसीसी और इतालवी क्रांति पर श्रमिक हलकों में नियमित रूप से बोलना शुरू किया। 1919 में उन्होंने समय-समय पर "द न्यू ऑर्डर: ए वीकली रिव्यू ऑफ सोशलिस्ट कल्चर" शुरू किया, जो वामपंथी कट्टरपंथी और क्रांतिकारियों के बीच लोकप्रिय हो गया। अगले कुछ वर्षों के लिए, ग्राम्स्की ने

अपना अधिकांश समय फैक्ट्री काउंसिल आंदोलन के विकास और उग्रवादी पत्रकारिता के लिए समर्पित किया। 8 नवंबर, 1926 को, उन्हें रोम में गिरफ्तार किया गया था और फासीवादी प्रभुत्व वाली इतालवी सरकार द्वारा लागू की गई "असाधारण कानूनों" की एक श्रृंखला के अनुसार एकांत जेल में डाला गया था। जेल में रहने के दौरान उनकी प्रिज़न नोटबुक उनके द्वारा लिखी गई थी। 27 अप्रैल, 1937 को उनका निधन हो गया।

स्रोत: (<https://www.marxists.org/archive/gramsci/intro.html>)

सबाल्टर्न स्टडी ग्रुप से जुड़े विद्वानों का मानना है कि सबाल्टर्न वर्गों के आदिवासी और किसानों द्वारा औपनिवेशिक काल में किए गए योगदान इतिहास में अनजाने ही रह गए हैं। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का अध्ययन विद्वानों के प्रमुख वर्ग द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास को लिखने में उन्होंने केवल कुलीनों के योगदान को स्वीकार किया। इस प्रकार, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी उन ऐतिहासिक आख्यानों को पुनर्स्थापित करने और लोगों की राजनीति और इतिहासकारों द्वारा नजरअंदाज किए गए इतिहास को पुनर्निर्मित करने का एक प्रयास था। सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि आदिवासी और किसान इतिहास की वस्तु नहीं हैं, बल्कि वे अपना इतिहास बनाते हैं। बी.आर. अम्बेडकर, रणजीत गुहा, डेविड हार्डमैन और अन्य सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य के प्रमुख पैरोकार हैं। अंबेडकर न केवल स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे, बल्कि दलितों के प्रति जाति आधारित अत्याचारों के खिलाफ व्यापक रूप से विरोध करते थे। रणजीत गुहा और डेविड हार्डमैन औपनिवेशिक भारत के विभिन्न आदिवासी और किसान विद्रोहियों को बहाल करने में लगे हुए हैं, जिन्हें प्रमुख इतिहास लेखन प्रथाओं द्वारा अनदेखा किया गया था।

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) उपाश्रित (सबाल्टर्न) परिप्रेक्ष्य क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) कौन से प्रमुख भारतीय विद्वान थे जिन्होंने उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया?

.....

.....

.....

.....

.....

4.2.1 रणजीत गुहा और सबाल्टर्न स्टडीज

सबाल्टर्न अध्ययन जो भारत में एक उपनिवेशवादी सिद्धांत के रूप में उभरा, लोगों के इतिहास को पुनः लिखने के बारे में है। इस परियोजना को ज्यादातर रणजीत गुहा और उनके सहयोगियों जैसे पार्थ चटर्जी, डेविड हार्डमैन, शाहिद अमीन, ज्ञानेंद्र पांडे, डेविड अर्नोल्ड, सुमित सरकार और दिपेश चक्रवर्ती द्वारा श्रेय दिया जाता है। सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास के अध्ययन के तरीकों का संबंध "सबाल्टर्न लोगों के इतिहास" से है। सबाल्टर्न इतिहास का मूल आधार नीचे से इतिहास या इतिहास के अभिजात्य वर्ग के विरोध के रूप में सबाल्टर्न लोगों के इतिहास को देखना था जो इतिहास बनाने में उनके योगदानों की अनदेखी करता है। धनगारे (1988) ने कहा है कि सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी दृष्टिकोण लोगों की राजनीति की भूमिका को उजागर करके एक संतुलन बहाल करना चाहता है जो कि भारतीय इतिहास में निभाई गई कुलीन राजनीति के खिलाफ है।

गुहा के अनुसार, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान सब अलटर्न इतिहासलेखन किसानों और जनजातीय आंदोलनों पर केंद्रित है क्योंकि इसे प्रमुख मुख्यधारा के अभिजात्य इतिहासकार ने अनदेखा किया है। उनके लिए, लोगों की राजनीति की उपेक्षा - और राष्ट्रवादी आंदोलन में सबाल्टर्न वर्गों के योगदान से भारतीय इतिहास अधूरा है। इसके अलावा, उनके अनुसार, अभिजात्य इतिहासकार में भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति है, जो स्वदेशी अभिजात वर्ग के एक आदर्शवादी उद्यम के रूप में है, जिसने लोगों को स्वतंत्रता से वंचित किया। इस तरह की इतिहासलेखन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व्यक्तिगत नेताओं या संगठनों और संस्थानों की प्रमुख ताकत के रूप में भूमिका पर जोर देती है। धनगारे (1988) का दावा है कि 'इस दृष्टिकोण के अनुयायियों का तर्क है कि अभिजात्य इतिहासलेखन, चाहे वह नव-उपनिवेशवादी हो या नव-राष्ट्रवादी किस्म का हो, ने हमेशा उस हिस्से को बड़ा चढ़ा कर दिया है जो भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण में निभाया गया अभिजात वर्ग है लेकिन लोगों (जनता) द्वारा उनके स्वतंत्र रूप से किए गए योगदानों की सही व्याख्याकम की है और उनके योगदान को स्वीकार करने में विफल रहा है।

गुहा (2013) ने अपने लेख को "औपनिवेशिक भारत के इतिहास के कुछ पहलू" शीर्षक दिया है, का तर्क है कि भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में इन अभिजात्यवादियों का वर्चस्व था जो औपनिवेशिक और बुर्जुआ राष्ट्रवादी थे। इस प्रकार के ऐतिहासिक लेखन से यह आभास मिलता है कि भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रवाद की चेतना केवल अभिजात वर्ग की उपलब्धि थी। इस संबंध में लोगों द्वारा किए गए योगदान की कोई प्रासंगिकता नहीं है। यद्यपि उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास और उसके निर्माण में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अपना योगदान दिया है। दूसरी ओर, इतिहास लेखन का अभिजात्य परिप्रेक्ष्य कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में उनकी अभिव्यक्ति और विद्रोह को चित्रित करता है। एकतरफा दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद को कुछ विशिष्ट नेताओं के करिश्मे की प्रतिक्रिया के रूप में मानता है। इस प्रकार, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी लोगों की राजनीति को नजरअंदाज करती है। सबाल्टर्न इतिहासकारों का तर्क है कि प्रभुत्वशाली कुलीनों की राजनीति के समानांतर राष्ट्रवादी आंदोलन में सबाल्टर्न वर्गों की भी अपनी राजनीति थी। उनकी राजनीति कुलीन राजनीति से उत्पन्न नहीं हुई थी और उनकी कुलीन राजनीति पर निर्भर नहीं थी। उनके लिए सबाल्टर्न एक स्वायत्त क्षेत्र है।

इस प्रकार, भारत में किसानों और जनजातीय आंदोलनों का अध्ययन करने में सबाल्टर्न दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह लोगों की राजनीति और कुलीन वर्ग की राजनीति के विरोध में है। धनगारे (1988) ने 'लोगों' और 'कुलीन वर्ग' के बीच एक

दोतरफा विभाजन के लिए तर्क दिया है। दोनों को राष्ट्रवादी आंदोलन के दो डोमेन के रूप में देखा जाता है। वह संरचनात्मक द्वंद्ववाद या समाज की संरचना में विभाजन का निर्माण करता है। लोगों की राजनीति प्रमुख समूहों की राजनीति से नहीं हुई थी। वे स्वदेशी लोग, हाशिए पर रहने वाले समूह और श्रमिक आबादी के वर्ग और शहर और देश में मध्यवर्ती वर्ग हैं। वे ऐसे लोगों के विविध समूह हैं जो सामान्य या समान विचारधारा साझा नहीं करते हैं, लेकिन उनके बीच दिलचस्प सामान्य विशेषता अभिजात वर्ग के प्रतिरोध के प्रति एक धारणा थी। उनके बीच विभाजन और विविधता मैत्री की समस्या पैदा करती है जो उनके बीच संभव नहीं थी।

गुहा का तर्क है कि कई बार भारतीय राष्ट्रवाद के अभिजात्य इतिहासकारव्यक्तिगत वृत्तान्त प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं, ने "देशी अभिजात वर्ग की अच्छाई जिनके कि औपनिवेशिक शासन के साथ विरोधी संबंध थे। यद्यपि, उनकी सहयोगवादी शोषक और उत्पीड़क के रूप में प्रवृत्ति थी, लोगों के हित को बढ़ावा देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे ब्रिटिश राज से सत्ता और विशेषाधिकार के लिए सबसे अधिक चिंतित थे (गुहा, 2013 :2)। गुहा के अनुसार, भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास भारतीय अभिजात वर्ग की आध्यात्मिक जीवनी है।

औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ औपनिवेशिक काल के दौरान किसानों, आदिवासियों और हाशिए पर पड़े समूहों का आंदोलन, विरोध, भिन्न तीव्रता को दर्शाता है। अभिजात वर्ग से स्वतंत्र उनकी लामबंदी और प्रतिरोध, स्वयं लोगों से उभरा। सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, अभिजात वर्ग और लोगों के मध्य द्विआधार का निर्माण करती है। अभिजात वर्ग की राजनीति में लामबंदी ऊपर से हासिल की गई थी जबकि नीचे की राजनीति में उपनिवेशवाद में लामबंदी हासिल की गई थी। कबीले, जाति, रिश्तेदारी, प्रादेशिकता, पारिवारिक नेटवर्क, वंचना जैसे पारंपरिक संस्थानों द्वारा सब अल्टर्न राजनीति और गतिशीलता को अधिक निर्देशित किया गया था। अभिजात वर्ग की राजनीति और गोलबंदी कानूनी और संवैधानिक विचारों से अधिक शासित थी। सबाल्टर्न लामबंदी अधिक हिंसक, आक्रामक और स्वतःस्फूर्त थी जबकि अभिजात वर्ग की एकजुटता सतर्क, नियंत्रित और उदारवादी थी।

इस प्रकार, सबाल्टर्न अध्ययन परियोजना एक वैकल्पिक इतिहास, 'लोगों का इतिहास' बनाने के लिए थी। गुहा औपनिवेशिक भारत में किसानों के विद्रोह के प्राथमिक पहलुओं (1983) में किसानों की बातें, किसानों की चेतना, उनके रहस्यवादी दर्शन और धार्मिकता और औपनिवेशिक विद्रोह के अपने अध्ययन में उनके समुदायों के सामाजिक बंधन के एक दिलचस्प वृत्तान्त की चर्चा करते हैं, इंडिया।

चूंकि वह एक मार्क्सवादी सबाल्टर्न इतिहासकार है, इसलिए वह अतीत की व्याख्या करते हैं ताकि इतिहासलेखन में आमूल-चूल परिवर्तन और चेतना विकसित हो सके। उनका मानना है कि किसान और आदिवासी विद्रोहियों को इतिहास की 'वस्तु' नहीं बल्कि उनके अपने इतिहास के 'निर्माता' माना जाना चाहिए। वे अपने स्वयं के परिवर्तनकारी चेतना से संपन्न हैं (धनगारे, 1988)।

बोध प्रश्न 2

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी (इतिहास लेखन) क्या देखती है?

.....

.....

2) सबल्टर्न परिप्रेक्ष्य में रणजीत गुहा के काम का मुख्य विषय क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) 'लोगों की राजनीति' पर धनागरे के विचार क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

4.2.2 डेविड हार्डमैन : देवी आंदोलन का अध्ययन

डेविड हार्डमैन, रणजीत गुहा की तरह भारत में भी सबल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी आंदोलन के प्रमुख सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के इतिहास पर ध्यान केंद्रित किया। अपने कार्यों में, उन्होंने ग्रामीण समाज और उनके दावे पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव पर जोर दिया। भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन के उनके विश्लेषण ने स्थानीय शक्ति संरचना और राष्ट्रवाद को समझने में नई अंतर्दृष्टि दी है। उन्होंने विशेष रूप से पश्चिमी भारत में औपनिवेशिक समय के दौरान स्थानीय किसानों की गतिविधियों और आदिवासी (आदिवासी) के दावे की भूमिका की जांच की। उन्होंने भारत में सबल्टर्न अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी भारत के आंदोलनों का विश्लेषण करने के लिए नृवंशविज्ञान और अभिलेखीय स्रोतों का उपयोग किया है। उन्होंने 1922-23 के दौरान गुजरात में हुए देवी आंदोलन का अध्ययन किया है। यह आदिवासी किसानों, साहूकारों, जमींदारों और शराब दुकान मालिकों के खिलाफ आदिवासी आंदोलन था।

हार्डमैन ने अपने लेख में "आदिवासी एसरशन इन साउथ गुजरात: देवी आंदोलन" (सबल्टर्न स्टडीज खंड 3) शीर्षक से आदिवासी समुदाय के लोगों पर शराब के हानिकारक प्रभावों के लिए शराब डीलरों के खिलाफ आदिवासियों के दावे के बारे में चर्चा की। 1878 के औपनिवेशिक अबकारी अधिनियम ने शराब के सभी स्थानीय निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया और जिले के मुख्यालय शहर में एक केंद्रीय आसवनी की अनुमति दी।

आदिवासी गाँवों में शराब बेचने के लाइसेंस के अलावा डिस्टिलरी चलाने के लिए शराब के सौदागरों ने सरकार को बड़ी राशि का भुगतान किया। शराब के वितरण ने निम्न जाति के लोगों, विशेषकर आदिवासियों को बुरी तरह प्रभावित किया। हार्डमैन अपने लेख में इसका प्रतिकूल प्रभाव बताते हैं। शराब विक्रेताओं पर कुछ नियंत्रण के बावजूद, वे कारखाने निर्मितकर शराब की बिक्री और आदिवासियों के गाँवों के समूहों के बीच इसके वितरण पर एकाधिकार रखते रहे। आबकारी अधिकारियों को शराब के अवैध निर्माण और अवैध भट्टियों के वितरण के लिए रिश्वत दी जा रही थी (हार्डमैन 2013: 203-4)। धन उधार देकर लाभ

और शराब बेचने से होने वाला लाभ बहुत बड़ा था और उनके द्वारा भूमि में निवेश किया गया था। इससे आदिवासी समुदाय प्रभावित हुआ और शराब पीने का आदी हो गया। उनकी जमीनों को शराब की दुकान मालिकों के पास गिरवी रख दिया गया या उन्हें बेच दिया गया।

आदिवासी किसान धीरे-धीरे महसूस कर सकते थे कि कैसे उनके ही गाँव में शराब के धंधेबाज उनका शोषण कर रहे हैं, हालाँकि वे शराब जैसे प्रमुख उत्पीड़कों के कारण इस तरह के शोषण के खिलाफ मुखर और विरोध करने में विफल रहे ... लेकिन शोषण की भावना के लिए एकजुट होकर उनका (शराब व्यापारियों का) विरोध किया, आदिवासी सब अलटर्न समूहों के बीच अब प्रमुख शराब सामंतों द्वारा दमन नहीं किया जा सकता है।

1922 में गुजरात के पश्चिमी भाग में एक नई परंपरा के रूप में एक दिलचस्प घटना हुई, जिसे हार्डिमान 'देवी आंदोलन' कहते हैं। हार्डिमान ने पाया कि 1922 की शुरुआत में गुजरात के तटीय इलाकों में सबाल्टर्न मछुआरा समुदायों में चेचक की महामारी फैल गई थी। उनका मानना था कि चेचक एक देवी के कारण हुआ था और उन्हें महामारी से छुटकारा पाने के लिए देवी को संतुष्ट करने की आवश्यकता है। उन्होंने देवता (देवी द्वारा शमा) को संतुष्ट करने के लिए समारोहों का आयोजन शुरू किया। यह शमा (महिलाओं के पास होने) के माध्यम से है कि देवी ने यह जानकारी दी कि अगर वे मछली, मांसखाना और शराब पीना, ताड़ी छोड़ देते हैं तो वह संतुष्ट हो जाएंगी। लोगों ने उसकी सलाह पर अमल किया। देवी आंदोलन को सलाबाई के नाम से जाना जाने लगा। धीरे-धीरे आदिवासियों के गाँवों में मनुष्यों के माध्यम से शर्मिंदगी की प्रक्रिया फैल गई थी और उन्होंने भी शैमनवाद का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। देवी के पास मौजूद महिलाओं को सुनने के लिए आदिवासी किसान एकत्र होते थे। नियमित रूप से स्नान करने के साथ-साथ शराब और मांस खाने और ताड़ी पीने से परहेज करने की देवी की मांग को पूरा करना होता था। इसका प्रभाव यह हुआ कि अधिकांश आदिवासियों ने पारसी शराब दुकान मालिकों और जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप आदिवासियों ने आपस में सामाजिक सुधार शुरू कर दिए। उनके कारण से शराब के कारोबारियों को नुकसान हुआ, हालाँकि शराबियों द्वारा आदिवासियों को शराब पीने की उनकी पुरानी आदतों को वापस लाने के प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और खुद को मना कर दिया और देवी के उनके विश्वास ने उन्हें शराब से बचने में मदद की। उपनिवेशवाद विरोधी मुख्यधारा के आंदोलन के दौरान, गांधीजी ने अपने आंदोलन और उनकी राजनीतिक आवाज़ की प्रवृत्ति के कारण आदिवासियों को अपने आंदोलन में शामिल किया, हरदिमान को मनाया। दक्षिण गुजरात में, आदिवासियों को औपनिवेशिक नीति का निष्क्रिय उद्देश्य माना जाता था। गुजरात के गांधीवादी राष्ट्रवादियों ने उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में मध्य वर्ग के साथ गठबंधन में एक साथ लाया। स्थानीय कथाओं, स्मृतियों, गीतों के साथ-साथ अभिलेखीय सामग्रियों की मदद से, हार्डिमान ने न केवल साहूकारों, शराबियों और शराब विरोधी आंदोलन के खिलाफ अपने दावे में आदिवासियों की भूमिका की जांच की बल्कि राष्ट्रवादी आंदोलन और सामाजिक सुधार में भी उनकी भूमिका की जांच की। बाहरी मदद से स्वतंत्र, उन्होंने धन उधारदाताओं और औपनिवेशिक संसाधन आधार की सामंती संरचना को तोड़ने की कोशिश की।

हार्डिमान ने गुजरात के खेड़ा जिले के स्थानीय क्षेत्रों में किसानों के बीच विस्तृत अध्ययन किया है। "उनके नृवंशविज्ञान विवरण से पता चलता है कि जिले के गाँवों के गरीब और भूमिहीन आदिवासी किसानों की तुलना में मध्य वर्गीय किसान अपेक्षाकृत कट्टरपंथी हैं।"

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) आदिवासियों के बारे में होर्डिमन ने देवी आंदोलन के अध्ययन के बारे में क्या बताया?

.....

.....

.....

.....

.....

4.2.3 उपाश्रित के रूप में दलित :बी. आर. अम्बेडकर

बी. आर. अम्बेडकर भारत के सबसे प्रमुख राजनीतिक विचारकों में से एक थे जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था और इसकी कठोरता को गंभीरता से देखा। उन्होंने दलितों और आदिवासी उपजातियों के मुद्दों को उठाया। उन्होंने निचली जाति के लोगों पर जाति व्यवस्था के प्रभाव का अध्ययन किया और उनके द्वारा सबसे अच्छा विश्लेषण किया गया। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती हिस्से के दौरान, इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया था। एक नीची जाति के परिवार में पैदा होने के कारण, अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन उस जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित कर दिया, जिसने दलित उपजातियों में भेदभाव आदि और उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया। विदेश में शिक्षित होने के बाद, वह भारत वापस आ गए और कानून का अभ्यास करने लगे। 1920 में, उन्होंने दलित हितों को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे में 'बहिष्कृत हितकारिणी' सभा का गठन किया और सरकार के सामने रखकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। वह न केवल जाति व्यवस्था के आलोचक थे बल्कि जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्होंने अन्य जातियों के साथ समान स्थिति और समान अवसरों का दावा करने के लिए दलितों की मदद की।

अम्बेडकर के प्रमुख लेखन हैं:

- 1) अछूत, वे कौन हैं?
- 2) शूद्र कौन थे?
- 3) राज्य और अल्पसंख्यक।
- 4) अछूतों की मुक्ति।
- 5) जाति का विध्वंस।

दलितों का उपाश्रित समूह भारतीय समाज में सबसे दबे-कुचले और भेदभाव वाले लोगों में से एक है। बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार, उपाश्रित समुदाय वे हैं जिन पर प्रमुख जातियों द्वारा भेदभाव किया जाता है। सामान्य तौर पर, निचली जाति के लोगों को हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था के अनुसार दलित कहा जाता है, लेकिन आम राजनीतिक समझ और विमर्श में अनुसूचित जाति के लोगों को दलित के रूप में नामित किया जाता है। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1935

के माध्यम से किया था। गांधीजी ने उन्हें हरिजन कहा था, जिसका अर्थ है 'ईश्वर की संतान'। दलितों को कुछ समय के लिए बाहरी जातियों, बहिष्कृत, दबे-कुचले वर्ग, 'अनुसूचित जाति, हरिजन', पूर्व-अछूत आदि नामों से जाना जाता है।

अंबेडकर ने दलितों को "एक प्रकार की जीवन दशा" के रूप में परिभाषित किया, जो उच्च जातियों की ब्राह्मणवादी विचारधारा के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व द्वारा दलित लोगों के शोषण, दमन और हाशिए पर खड़ा है। वे हिंदू समाज के वर्ण योजना की जाति की सीढ़ी में सबसे निचले तबके के हैं, जिन्हें ज्यादातर अछूत कहा जाता है। अंबेडकर जाति के विचार और उसके संबंधित गुणों जैसे पेशे और पदानुक्रम के प्रति आलोचनात्मक थे। उन्होंने जाति को एक प्राकृतिक विभाजन नहीं माना, बल्कि सामाजिक भेदभाव की श्रेणी में रखा। उनका मानना है कि भारतीय समाज में दलित सबसे अधिक पददलित (निचले तबके का) लोग हैं, जहां वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। उन्हें समाज के प्रदूषित तबके के रूप में माना जाता रहा है जहाँ उनका स्पर्श और यहाँ तक कि उनकी छाया भी सवर्णों को प्रदूषित कर सकती थी।

अंबेडकर द्वारा जाति व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक मत्वपूर्ण 'श्रेणीबद्ध असमानता' का विचार था। वह असमानता और वर्गीकृत असमानता के बीच अंतर करते हैं। असमानता को त्वचा के रंग, नस्लीय और व्यावसायिक या काम के अंतर जैसे विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। पश्चिमी समाजों में काले और सफेद रंग के अंतर आम हैं। इन्हें नस्लीय अंतर के रूप में जाना जाता है। नस्लीय अंतर के कारण सामाजिक विभाजन पूर्वाग्रहों, विघटन, अपेक्षाकृत श्रेष्ठ माने जाने वाली नस्ल के खिलाफ किए जा रहे उत्पीड़न का आधार है। इसी तरह, औद्योगिक समाजों में, विभिन्न कार्य पदों के आधार पर मतभेद होते हैं। ये श्रमिक वर्ग (सर्वहारा) और प्रमुख वर्ग (बुर्जुआ) हैं। उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और रुचियां एक-दूसरे से भिन्न हैं। वे असमान वर्ग के हैं और उनके बीच परस्पर विरोधी संबंध सदा के लिए हैं। औद्योगिक समाजों के प्रशासनिक और व्यावसायिक स्तरों पर भी सुपर-ऑर्डिनेट्स (प्रशासनिक और पेशेवर कुलीन वर्ग और नौकरशाह) और उप-ऑर्डिनेट्स (जो सुपर-ऑर्डिनेट्स के तहत काम करते हैं) हैं। वे असमान वर्ग भी हैं जहां उनके बीच असमानता उत्पादक कार्य की प्रकृति पर आधारित है जिसमें वे लगे हुए हैं। त्वचा के रंग, नस्ल और व्यावसायिक या काम के अंतर के आधार पर इस तरह की असमानताएं, असमानताओं के विभिन्न रूप हैं, लेकिन श्रेणिक असमानता, असमानता का एक अनूठा रूप है जो विशेष रूप से भारतीय समाज की विशेषता है, हिंदू सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में जहां जाति की निर्दिष्ट स्थिति अंतर और असमानता का आधार है। हिंदू जाति व्यवस्था चार वर्णों में एक श्रेणीबद्ध पदानुक्रमिक प्रणाली है, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ३३ अछूत जाति व्यवस्था के बाहर हैं। वे जाति व्यवस्था में सबसे निचले दर्जे के लोग हैं। वे न केवल दूसरों से अलग हैं, बल्कि जन्म से भी असमान हैं और तदनुसार उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति निर्धारित की जाती है।

अंबेडकर के अनुसार, भारत में जाति व्यवस्था क्रमबद्ध असमानता का एक अनूठा रूप है जहां शूद्रों और अछूतों को छोड़कर, बाकी लोग पारंपरिक सामाजिक स्तर में अपनी श्रेणीबद्ध सामाजिक स्थिति के अनुसार विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं। अशिक्षित जाति पदानुक्रम के शीर्ष पर ब्राह्मणों को जाति विचारधारा का पूर्ण लाभ मिलता है। उनकी सामाजिक और कर्मकांड की स्थिति सर्वोच्च है, लेकिन शूद्र और अछूत जाति के पदानुक्रम में पूर्ण पीड़ित हैं। इस प्रकार, जाति व्यवस्था में लोगों को पदानुक्रमित आदेशों में विभाजित और व्यवस्थित किया जाता है। इसे अंबेडकर ने ग्रेडेड असमानता कहा है। उसके लिए, असमानता एक सामाजिक स्थिति है जहां सामाजिक स्थिति दी गई है, पूर्वनिर्धारित है, और उस जाति में

जन्म से प्राप्त की जाती है और गैर-अछूत (उपलब्धि आधारित) परिवर्तनों को छोड़कर नहीं बदला जा सकता है। इस तरह की एक श्रेणीबद्ध प्रणाली, निर्दिष्ट स्थिति में बदलाव के लिए बहुत कम या गुंजाइश या विकल्प नहीं छोड़ती है। उनके पास जाति व्यवस्था की दमनकारी वास्तविकता से लड़ने का कोई विकल्प नहीं है, हालांकि परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन जातिगत व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाती है और जातिविहीन समाज नहीं निर्मित होता है। सामाजिक असमानता के अन्य रूपों में, श्रमिक वर्ग के पास भेदभावपूर्ण प्रथाओं के लिए उद्योग के मालिक के खिलाफ लड़ने का विकल्प है, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि जाति की विचारधारा जाति के अनुसार, उच्च जाति के अधिकार और विशेषाधिकार हैं जाति पदानुक्रम में उनके नीचे निचली जातियों के ऊपर। (इस संबंध में पढ़ने के लिए, प्राचीन भारत में अंबेडकर द्वारा क्रांति और काउंटर क्रांति देखें)। इसी प्रकार, जाति श्रेणियों के अधिकारों को क्रमिक परिवर्तन को लगभग असंभव बना दिया जाता है।

अंबेडकर जाति व्यवस्था के कामकाज और सामाजिक बहिष्कार और दलितों विशेषकर निचली जाति के भेदभाव की प्रक्रिया के लिए काफी आलोचनात्मक हैं। गांधीजी के विचार और जाति से कोई लेना-देना नहीं रखने वाले धार्मिक संस्थानों के लिए भी वे बहुत आलोचनात्मक थे। वर्ण का कानून पैतृक व्यवसाय का पालन करके हमें रोटी कमाना सिखाता है और यह हमारे अधिकारों को नहीं बल्कि हमारे कर्तव्यों को परिभाषित करता है (1990: 108)।

अंबेडकर का तर्क है कि जाति हित से अलग काम करती है। यह मैनुअल श्रम से बौद्धिकता को डिस्कनेक्ट करता है। यह महत्वपूर्ण हित साधने के अधिकार से इनकार करता है। यह लामबंदी को रोकता है। सभ्य समाज को श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम का विभाजन श्रम के अप्राकृतिक विभाजन के साथ नहीं होता है। जाति एक पदानुक्रम है जिसमें श्रम का विभाजन एक के ऊपर एक किया जाता है। किसी अन्य देश में श्रम का विभाजन श्रम के उन्नयन के साथ नहीं होता है। इस प्रकार, ग्रेडेड असमानता भारत में जाति व्यवस्था की आत्मा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी जातियों ने इस तरह के विभाजन को आत्मसात कर लिया है। ग्रेडेड असमानता के आत्मसातीकरण के परिणामस्वरूप सभी जातियों या आवश्यक सुधारों के लिए जाति व्यवस्था में जातियों के संयोजन को लाने में विफलता हुई है।

इसके अलावा, अंबेडकर के अनुसार, श्रेणीबद्ध असमानता न केवल सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी निचली जातियों को बाहर करती है। उदाहरण के लिए, महार जाति के दलितों को बुनाई विभाग में काम का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि वे शुद्धता और प्रदूषण के कारक के कारण धागे को छूने वाले नहीं हैं। निचली जाति की उपजातियों द्वारा जाति विचारधारा का आंतरिककरण उन्हें उच्च जातियों या मालिकों के लिए आभारी बनाता है। यह उन्हें उनकी ताकत से अनभिज्ञ बनाता है जो उन्हें अमान्य बनाए रखता है। वे विनम्र हो जाते हैं और उनकी विनम्रता उनके अधीनता के प्रमुख मुद्दे में से एक है।

इस प्रकार, भारत में जाति-विरोधी आंदोलन में अंबेडकर केंद्रीय व्यक्ति बन गए। उन्होंने उच्च जातियों द्वारा दलितों पर अत्याचार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। सभा का मकसद शिक्षित, संगठित और आंदोलित करना था। उनका मानना है कि जब तक दलितों का उत्थान और संघर्ष नहीं होगा, वे अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं करेंगे। स्व-जागरण जाति आधारित अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। उन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और भेदभाव की अपनी विचारधारा का पता लगाया और कहा कि मनुस्मृति और इस तरह

के अन्य लेखन की पवित्र हिंदू पांडुलिपियों ने जाति उत्पीड़न को वैध बनाया है। | ऐसे ग्रंथ सामाजिक भेदभाव के आधार को एक जन्म के आधार पर निर्धारित करते हैं। इसलिए, उन्होंने ऐसे ग्रंथों को नष्ट करने की वकालत की। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाकर अम्बेडकर ने एक महान संघर्ष (महा-संघर्ष) की ओर कदम बढ़ाया और जातिगत पदानुक्रम और अस्पृश्यता के पौराणिक आधार को नकारने के लिए सत्याग्रह किया।

बोध प्रश्न 4

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार उपाश्रित (सबाल्टर्न) समुदाय क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) बी. आर. अम्बेडकर ने दलितवाद को कैसे परिभाषित किया?

.....

.....

.....

.....

.....

3) श्रेणीबद्ध असमानता क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

4.3 सारांश

इस इकाई में हमने सबाल्टर्न की अवधारणा और रणजीत गुहा, डेविड हार्डिराम जैसे विद्वानों और बी. आर. अम्बेडकर के विचारों की व्याख्या की। आदिवासी और दलित सबाल्टर्न दृष्टिकोण की चर्चा हमें सबाल्टर्न के विचार का पता लगाने और सबाल्टर्न दृष्टिकोण से समाज पर चर्चा करने की गुंजाइश देती है। इतिहास का सबाल्टर्न लेखन बाह्य और आंतरिक से एक समालोचना है। 'निचले स्तर की आवाज' को छोड़ा नहीं जा सकता और

इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी और सबाल्टर्न स्टडीज के सिद्धांत और कार्यप्रणाली पर बहस इतिहासकारों और सामाजिक वैज्ञानिकों को किसानों और अन्य उपाश्रित वर्गों के दावों और राजनीति पर ध्यान देने की गुंजाइश देती है।

4.5 संदर्भ

धनगारे, डी. एन. 1988. " सबाल्टर्न कनसियसनेस एंड पोपुलिज़्म: टु अप्रोचेस इन द स्टडी ऑफ सोसल मोवमेंट्स इन इंडिया". सोसल साइंटिस्ट. वोल. 16, नं. 11 . 18-35

गांधी, एम. के. 1990, ' ए विंडीकेशन ऑफ कास्ट', ऐनिहिलेशन ऑफ कास्ट: अन अनडेलीवर्ड स्पीच, अर्नोल्ड पब्लिशर्स, न्यू डेलही.

गुहा, रणजीत. 1983. एलीमेंटरी आस्पेक्ट्स ऑफ पिजंट इनसरजेंसी इन कोलोनीयल इंडिया. डेलही: ओयूपी.

.....रणजीत. 2013. " ऑन सम आस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ कोलोनीयल इंडिया" इन सबाल्टर्न स्टडीज़ राइटिंग ऑन साउथ एशियन हिस्टरी एंड सोसाइटी. वोल.1. न्यू डेलही: ओयूपी

हरदिमन, डेविड. 2013. " आदिवासी असर्शन इन साउथ गुजरात: द देवी मोवमेंट" इन रणजीत गुहा (एड). सबाल्टर्न स्टडीज़ राइटिंग ऑन साउथ एशियन हिस्टरी एंड सोसाइटी. वोल. 1. न्यू डेलही: ओयूपी

नायक, सी. डी. 2003. थाट्स एंड फिलॉसफ़ि ऑफ डॉ बी . आर . अंबेडकर. न्यू डेलही: सरूप - संस

वसंत मून (एताल) डॉ. बाबा साहब अंबेडकर : रेटिंग एंड स्पीचेस. बॉम्बे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वोल. 7: 1989. 211- 226

<https://www.marxists.org/archive/gramsci/intro.htm>_accessed on 28/08/2018

4.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

- 1) उपाश्रित (सबाल्टर्न) शब्द का अर्थ है अवर श्रेणी के लोगों की उनकी विभिन्न विशेषताओं जैसे कि आर्थिक स्थिति, नस्ल, जातीयता, लिंग, जाति, यौन अभिविन्यास। ये लोग समाज में ऐसी विशेषताओं के लिए हाशिए पर हैं। यह नीचले स्तर से समाज को समझने का एक तरीका है।
- 2) उपाश्रित (सबाल्टर्न) परिप्रेक्ष्य के प्रमुख विद्वानों में रणजीत गुहा, डेविड हार्डमैन, पार्थ चटर्जी, शाहिद अमीन, ज्ञानेंद्र पांडे, डेविड अर्नोल्ड, सुमित सरकार, दिपेश चक्रवर्ती, अंबेडकर और अन्य हैं।

बोध प्रश्न 2

- 1) सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी लोगों की राजनीति को नजरअंदाज करती है।
- 2) गुहा "औपनिवेशिक भारत में किसानों के विद्रोह के प्राथमिक पहलू" (1983) में 19वीं सदी के अपने अध्ययन में किसानों के दावों, किसानों की चेतना, उनके रहस्यवादी

दर्शन और धार्मिकता और उनके समुदायों के सामाजिक बंधन का एक दिलचस्प विवरण है, उनके द्वारा 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह आदि।

- 3) धनागरे समाज की संरचना में विभाजन को मोटे तौर पर देखते हैं। लोगों की राजनीति प्रमुख समूहों की राजनीति से नहीं हुई थी। वे स्वदेशी लोग, हाशिए पर रहने वाले समूह और श्रमिक आबादी के वर्ग और शहर और देश में मध्यवर्ती वर्ग हैं। वे ऐसे लोगों के विविध समूह हैं जो सामान्य या समान विचारधारा साझा नहीं करते हैं, लेकिन उनके बीच दिलचस्प सामान्य विशेषता अभिजात वर्ग के प्रति प्रतिरोध की उनकी एक धारणा थी।

बोध प्रश्न 3

- 1) हार्डिमन ने स्थानीय आख्यानों, स्मृतियों, गीतों के साथ-साथ अभिलेखीय सामग्रियों के माध्यम से समझाया, आदिवासियों की भूमिका न केवल उनके उधारदाताओं, शराबियों और शराब विरोधी आंदोलन बल्कि राष्ट्रवादी आंदोलन और सामाजिक सुधार में भी है। किसी भी बाहरी मदद से स्वतंत्र, वे अर्थात् आदिवासियों ने धन उधारदाताओं और औपनिवेशिक संसाधन आधार की सामंती संरचना को तोड़ने की कोशिश की।

बोध प्रश्न 4

- 1) बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार, सबाल्टर्न समुदाय वे हैं जिन पर प्रमुख जातियों, समुदायों द्वारा भेदभाव किया जाता है।
- 2) अम्बेडकर ने दलितों को "एक प्रकार की जीवन दशा" के रूप में परिभाषित किया है, जो उच्च जातियों की ब्राह्मणवादी विचारधारा के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व द्वारा दलित लोगों के शोषण, दमन और हाशिए की विशेषता है।
- 3) ग्रेडेड असमानता विभिन्न समूहों का पदानुक्रमित क्रम है जहां एक समूह को दूसरे से बेहतर माना जाता है। साथ ही श्रेष्ठ समूह को उसके ऊपर के समूहों के संबंध में हीन माना जाता है। अम्बेडकर ने भारत में जाति व्यवस्था को विस्तृत करने के लिए क्रमिक असमानता के विचार पर मंथन किया जहाँ शूद्रों को जाति पदानुक्रम में सबसे हीन समूह माना जाता है और ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ समूह हैं। वैश्य और क्षत्रिय बीच में हैं जहां वे शूद्र से श्रेष्ठ हैं लेकिन पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों से नीचे माने जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में जन्म के आधार पर असमानता है।

